



घूँघटा की बग़ावत

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 25 अंक : 02

गोरखपुर, 06 जुलाई 2025 रविवार

पृष्ठ : 6

मूल्य : 2

ठाकरे बंधुओं की रैली हिंदू विरोधी और जिहादी सोच से प्रेरित : नितेश राणे

पुणे। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने मुंबई में ठाकरे बंधुओं (उद्धव और राज) की संयुक्त रैली को लेकर शनिवार को उन पर निशाना साधते हुए इस रैली को हिंदू विरोधी और जिहादी सोच से प्रेरित करार दिया।

राणे ने आरोप लगाया कि उद्धव और राज की इस संयुक्त रैली का उद्देश्य समाज को बांटना और राज्य

को कमजोर करना है। दो दशक के बाद उद्धव और राज ने शनिवार को सार्वजनिक मंच साझा किया और 'आवाज मराठीच' नामक विजय सभा का आयोजन किया जिसका उद्देश्य राज्य के स्कूलों में कक्षा एक से तीसरी के रूप में हिंदी को शामिल



करने संबंधी सरकार द्वारा पहले जारी किए गए दो सरकारी आदेशों को वापस लेने का जश्न मनाया था। राणे ने इस रैली से एक दिन पहले शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा, हम हिंदू हैं और मराठी होने पर गर्व करते हैं। जिस तरह से जिहादी हमारे समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, ये लोग भी वैसा ही कर रहे हैं। चाहे वह हिंदू राष्ट्र के विचार के खिलाफ काम करने वाले (प्रतिबंधित) पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) हो या स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी), ये दोनों (उद्धव और राज ठाकरे) कोई अलग नहीं हैं। ये लोग महाराष्ट्र को

कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता राणे ने ठाकरे बंधुओं की संयुक्त रैली पर निशाना साधते हुए कहा, वली की सभा का उद्देश्य हिंदुओं और मराठी लोगों को बांटना है। इसकी तुलना ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम), पीएफआई या सिमी की रैलियों से की जा सकती है। इसे राज्य में हिंदुओं को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। रैली के बाद नल बाजार (मुंबई का एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र) में मिठाई बांटी जाएगी और पटाखे फोड़े जाएंगे।

राज्य के मत्स्य पालन एवं बंदरगाह विकास मंत्री ने आरोप लगाया कि यह हिंदू विरोधी रैली है। नितेश राणे उद्धव ठाकरे के धुर विरोधी माने जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के पुत्र हैं। हालांकि, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने ठाकरे बंधुओं की रैली को लेकर अलग विचार व्यक्त किए।

मुनगंटीवार ने कहा, अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ रहे हैं तो यह अच्छी बात है। उन्हें हमारी शुभकामनाएं हैं। दोनों भाइयों को एक होना चाहिए और एक रहना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो दोनों पक्षों को विलय पर भी विचार करना चाहिए।

व्योग मार्ग वैमानिकी यात्रा दिनोंदिन असुरक्षित एवं भयाक्रांत

अहमदाबाद की विमान दुर्घटना से पहले दिसंबर - 2024 के अंतिम सप्ताह में दक्षिण कोरिया का एक क्षेत्रीय विमान विमान स्थल पर उतरते हुए दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस घटना में 17 लोग मारे गए थे। अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संघटन के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 19वीं शताब्दी में 28 जून 1856 से लेकर 11 जुलाई 1897 तक कुल पांच वायु वाहन (अर्थात हाइड्रोजन गुब्बारा) दुर्घटनाग्रस्त या अदृश्य हुए थे। 20वीं सदी में सन 1901 से 1919 तक कुल 13 वायु कहनों के साथ दुर्घटना हुई। इसमें 11 लोग रहस्यमयी ढंग से अदृश्य हुए। इसी सदी में 1920 - 1939 की समयावधि में हुई 49 विमान दुर्घटनाओं में जून 195 लोगों में से अधिसंख्यक का पता नहीं चल पाया था। जैसे-जैसे दुनिया में वैज्ञानिक औद्योगिक यांत्रिक एवं प्रौद्योगिकीय उन्नति होती रही। उसी गति से वायुयान दुर्घटनाग्रस्त अथवा दुर्घटना में अदृश्य होते रहे हैं। सन 1940 और 1959 की अवधि में 75 विमान आकाश में अनिर्वचित्र हुए इनमें 1960 लापता थे। सन 1960 से 1976 के मध्य 46 विमानों की दुर्गाति हुई इसमें 531 व्यक्ति काल कवलित हुए। इसी प्रकार से 32 विमान-दुर्घटनाओं में 220 लोगो ने प्राण गंवाए। 21वीं सदी में भी विमान दुर्घटनाओं की आवृत्ति कम नहीं हुई सन 2000 से 2019 के बीच कुल 18 घटनाओं में 295 लोगों की जानें गईं। इसी अवधि 6 मार्च, 2014 को मलेशिया एयरलाइंस के बोइंग 777-200ई आर की दुर्घटना भी सम्मिलित है। सन 2019 तक यह सबसे बड़ी विमान दुर्घटना थी। इसमें 2.39 लोग सवार थे जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चला है। इस तरह व्योग मार्ग वैमानिकी यात्रा दिनोंदिन असुरक्षित एवं भयाक्रांत होती जा रही है।

देश दुनिया की विमानन कंपनियों और विमान एवं विमान से संबंधित उपकरणों को बनाने वाली कंपनियों को व्यापक स्तर पर यह प्रयास करना चाहिए कि विमानों की दुर्घटनाओं के प्रमाणिक कारण खोजे उनके निस्तारण की दिशा में कार्य करें और भविष्य में हर संभावित दुर्घटना से सुरक्षित रहने के उपाय करें। भारत देश के शासन और वैमानिकी शिक्षण प्रशिक्षण के लिए कार्यरत प्रतिष्ठानों को विमान दुर्घटनाओं के परिचित अपेक्षित और संभावित कारणों की सघन जांच पड़ताल करनी होगी ताकि वायु यात्रा हर दृष्टि से सुरक्षित किया जा सके।

वाली एयर इंडिया की उड़ान - 855 मुंबई से उड़ान भरने के बाद अरब सागर में गिर गई थी। यह घटना एक जनवरी 1978 को हुई थी। विमान में सवार सभी यात्री-213 लोगों की मौत हो गई। फिर इंडियन एयर लाइंस की उड़ान 113 वर्ष 1988 में 19 अक्टूबर को अहमदाबाद विशाल स्थल दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें 133 लोग मारे गए। सन-1990 में 14 फरवरी को उड़ान संख्या 605 बेंगलुरु विमान स्थल पर दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 146 लोग मारे गए। सन-1996 में से 12 नवंबर को हरियाणा के चरखी दादरी में कजाकिस्तान एयरलाइंस की उड़ान संख्या-1907 की दुर्घटना में 349 लोग मारे गए थे। उड़ान संख्या - 1412 वर्ष 2000 के 17 जुलाई को बिहार के पटना के धनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्र में हादसे का शिकार हुई जिसमें 60 लोग मारे गए थे।

एयर इंडिया को एक्सप्रेस उड़ान - 1344 जो थी वह 7 अगस्त 2020 को कोझीकोड कालीकट अंतर्राष्ट्रीय विमान स्थल के रनवे पर फिसलने के कारण दो हिस्सों में बंट गई जिसमें 21 लोग मारे गए। इस घटना के आलोक में प्रगति एवं विकास का जो अभिशप्ट पक्ष दिखाई दिया है उसने लोगों में असुरक्षा के गहरे भाव भर दिए हैं। विमान में सवार लोग साधारण नहीं थे। वे धनी और स्थानीय लोग थे। इसलिए विमान या विमान सेवाओं में कोई कमी रही होगी इसकी भावना भी नहीं के बराबर है। अंतरराष्ट्रीय विमान एजेंसियों के अनुसार, अधिकतम विमान दुर्घटनाएं उड़ान भरने और रन वे पर उतरने की समयावधि में होती है। कुल दुर्घटनाओं में 35 प्रतिशत तो उड़ान भरने या उसके तुरंत बाद ही होती है।

विमान दुर्घटनाओं की त्रासदी झेलने वाले शीर्ष दस देशों में अमेरिका पहले स्थान पर है। सोचने वाली बात ये है कि जो दुनिया का सबसे समृद्ध और आधुनिक देश है वहीं क्योंकि विमान की दुर्घटनाओं को रोकने में विफल है।

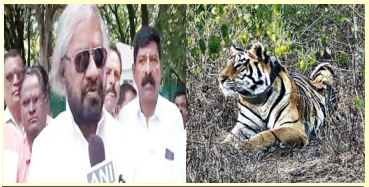
कर्नाटक में पांच बाघों की मौत पर वन मंत्री ने बरती सख्ती

बेंगलुरु। कर्नाटक के वन मंत्री इश्वर खांडेरे ने माले महादेश्वर (एमएम) पहाड़ियों में पांच बाघों की अप्राकृतिक मौत के संबंध में लापरवाही और कर्तव्य निर्वहन में चूक के लिए दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि मंत्री ने इस मामले में उप वन संरक्षक (डीसीएफ) वाई चक्रपाणि को निलंबित करने की भी सिफारिश की है। एमएम हिल्स के हुग्याम रेंज में 26 जून को एक मादा बाघिन और उसके चार शावक मृत पाए गए थे।

खांडेरे ने चक्रपाणि के आचरण की विभागीय जांच की भी सिफारिश की। घटना के बाद तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। खांडेरे का यह निर्णय अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एपीसीसीएफ)

कर्तव्य निर्वहन में चूक एवं लापरवाही के कारण अधिकारियों का निलंबन



कुमार पुष्कर की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आया।

घटना की जांच के लिए इस समिति का गठन किया

गया था। मंत्री ने समिति को 10 जुलाई तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। खांडेरे के कार्यालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, बाघों की अप्राकृतिक मौत मामले में अधिकारियों की लापरवाही और कर्तव्यों का पालन न करने के स्पष्ट सबूत हैं जिनके आधार पर मंत्री ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से डीसीएफ वाई चक्रपाणि के निलंबन की सिफारिश की है।

बयान में कहा गया है कि सहायक वन संरक्षक गजानन हेगड़े और संबंधित क्षेत्र के रेंज वन अधिकारी मंदेश को निलंबित कर दिया गया है क्योंकि वे गश्ती कर्मचारियों की प्रभावी निगरानी करने में विफल रहे और वन संरक्षण के अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में घोर लापरवाही बरती।

विदेश नीति के मोर्चे पर भी युनुस की टिप्पणियां विवादित रही है। चीन यात्रा के दौरान उनका बयान कि- पूर्वोत्तर भारत लैंड लॉकड है और बांग्लादेश 'ओशन गार्डियन बन सकते हैं, ने भारत-बांग्लादेश संबंध में तनाव पैदा किया इससे न केवल भारत असहज हुआ है बल्कि बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में भी उनके इरादों पर सवाल खड़े हो गए हैं। विदेशनीति जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अंतरिम सरकार को तटस्थ और संयमित रहना चाहिए था विशेषकर तब जब उनकी भूमिका केवल चुनाव कराने और सत्ता हस्तांतरण तक सीमित हो।



प्रतीत होती है। खासकर तब जब इसी बीच जमात-ए-इस्लामी पर से पतिबंध हटा लिया गया है इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर भी संदेह उठ रहे हैं। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को भी बीएनपी झुकाव वाला बताया है और उसकी संरचना में बदलाव करले की मांग की है। साथ ही. अप्रैल 2026 में चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव भी अव्यवहारिक लगता है क्योंकि उस समय स्कूलों की परीक्षाएं होती हैं, प्री-मानसून उपानों का खतरा होता है और चुनाव के लिए आवश्यक प्रशासनिक सहयोग नहीं मिल पाता है। बांग्लादेश में पारंपरिक रूप से दिसंबर में चुनाव कराए जाते रहे हैं। और वही तिथि उपयुक्त मानी जाती है। अगर बांग्लादेश को राजनीतिक स्थिरता और लोकतंत्र की बहाली की दिशा में आगे बढ़ना है, तो युनुस को अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव लाना होगा। अवामी लीग को चुनाव प्रक्रिया में वापस लाना ही एकमात्र रास्ता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि अगली सरकार को व्यापक समर्थन प्राप्त हो अन्यथा यह चुनाव न तो जनादेश को प्रतिबधित करेगा न ही देश में स्थायित्व बनाएगा। बांग्लादेश पहले ही गहरे संकट में है। अब समय है कि अंतरिम सरकार राजनीतिक संवाद को फिर से शुरू करे, सभी पक्षों को शामिल करें और अपने वादों को निभाए। अन्यथा देश एकबार फिर अराजकता के गर्त में चला जाएगा। जहां से उबरना कठिन होगा। अवामी लीग बांग्लादेश की राजनीति में केवल पार्टी ही नहीं है यह उस आंदोलन का प्रतीक है जिसके बल पर बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली। उसके बिना कोई भी राष्ट्रीय चुनाव न केवल अपूर्ण होगा

बल्कि उसकी वैधता भी संदेह के घेरे में होगी। आ जाएगी। युनुस द्वारा घोषित चुनाव प्रक्रिया अगर पार्टी को बाहर रख कर कराई जाती है, तो यह निष्पक्ष व समावेशी नहीं मानी जा सकती है इससे राजनीतिक संकट और गहराएगा और देश में स्थायित्व के बजाए और अधिक अराजकता फैल सकती है। मोहम्मद युनुस गत वर्ष 7 अगस्त, 2024 को अंतरिम सरकार के नेता बने जब छात्रों के नेतृत्व में हुए जनांदोलन ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बाहर कर दिया। उस समय व्यापक हिंसा हुई जिसमें सुरक्षा बलों द्वारा 300 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई। थी। इस आंदोलन की शुरुआत सरकारी नौकरियों में 1971 के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को आरक्षण देने के खिलाफ हुई थी लेकिन धीरे-धीरे यह आंदोलन व्यापक राजनीतिक असंतोष का रूप ले बैठा। शेख हसीना के भारत भागकर आने के बाद युनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार ने सुधार, न्याय और चुनाव को अपना मुख्य एजेंडा बताया परंतु जिस तरह से युनुस की सरकार ने आवामी लीग को प्रतिबंधित किया है उससे उसकी मंशा पर सवाल उठाते हैं। उसने यह कदम मई-2025 में उठाया इसके लिए एंटी टेररिज्म एक्ट और इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक्ट का सहारा लिया गया। पार्टी को 2024 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और लगभग 1,400 लोगों की मृत्यु के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार ठहराया गया। यह एक अत्यंत कठोर और विवादास्पद निर्णय है क्योंकि यह पूरी पार्टी को एक ही ब्रश से रंग देता है जबकि लोकतंत्र में सामूहिक दण्डकी अवधारणा स्वीकार्य नहीं है।

गुरु-शिष्य के आदर्शतम रिश्ते की मिसाल गोरक्षापीठ

गोरक्षपीठ की परंपरा, लोगों को शिष्य बनाने की नहीं है। पर, उत्तर भारत की प्रमुख व प्रभावी पीठ और अपने व्यापक सामाजिक सरोकारों के नाते इस पीठ के प्रति लाखों-करोड़ों लोगों की स्वाभाविक सी श्रद्धा है। गोरखपुर/ पूर्वांचल की तो यह अध्यक्षीय पीठ है। पीठ का हर निर्णय अमूमन हर किसी को स्वीकार्य होता है। खासकर पर्व और त्योहारों के मामले में।



की परंपरा के अनुसार वह लोककल्याण को सर्वोपरि रखते हुए समाज, संस्कृति, सामाजिक समरसता को समृद्ध कर रहे हैं।

अपने समय में योगी के लिए

बड़े महाराज का आदेश बीटो जैसा था

अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवेधनाथ के प्रति उनकी श्रद्धा कितनी गहरी थी, इसके साक्षी पीठ से जुड़े लोग हैं। अपने समय में ब्रह्मलीन महंत अवेधनाथ का आदेश उनके शिष्य योगी आदित्यनाथ के लिए ह्रदवीटो पॉवरफुल जैसा था। आज भी पद के अनुरूप अपनी तमाम व्यस्तताओं में से समय निकालकर वह जब भी गोरखनाथ मंदिर पहुंचते हैं तो सबसे पहले अपने ब्रह्मलीन गुरुदेव का ही आशीर्ष लेते हैं। यह सिलसिला उनके मठ में रहने तक जारी रहता है। गुरु शिष्य का यही संबंध योगी जी के गुरुदेव और उनके गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ में भी था।

गुरु पूर्णिमा और साप्ताहिक पुण्यतिथि

समारोह में गुरु शिष्य परंपरा की

मिसाल बनती है पीठ

हर गुरुपूर्णिमा और सितंबर में गुरुजनों को श्रद्धा निवेदित करने के लिए आयोजित साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह के दौरान अपने गुरुओं को पीठ याद करती

कन्नड़ के खिलाफ टिप्पणी नहीं करने

का बेंगलुरु की अदालत का निर्देश

बेंगलुरु। बेंगलुरु की एक अदालत ने शुक्रवार को अभिनेता कमल हासन को कन्नड़ के खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया। अदालत ने उनपर कन्नड़ भाषा, साहित्य, भूमि व संस्कृति के खिलाफ कोई भी बयान देने, पोस्ट करने, लिखने, प्रकाशित करने पर रोक लगाई है। अतिरिक्त नगर एवं सत्र दायीनी न्यायाधीश ने कन्नड़ साहित्य परिषद (के एसपी) के अध्यक्ष महेश जोशी के माध्यम से दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। केएसपी ने हासन को कन्नड़ और संस्कृति के खिलाफ कोई भी अपमानजनक बयान देने से रोकने का भी अनुरोध किया था। अदालत ने कमल हासन को सम्मन जारी करने का भी आदेश दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 अगस्त की तारीख तय की। हासन ने अपनी फिल्म उग लाइफ के प्रचार कार्यक्रम के दौरान हाल ही में कहा था कि कन्नड़ तमिल से पैदा हुई है। अभिनेता के बयान के बाद कन्नड़ समर्थक समूहों और सांस्कृतिक संगठनों ने व्यापक आक्रोश व्यक्त किया था।



फैक्ट्री के धमाकों को रोकना बड़ी चुनौती

तेलंगाना के संगरेड्डी जिले के पासमेलारम फेज एक इलाके में एक केमिकल फैक्टरी में हुए विस्फोट में 34 कर्मचारियों की मौत हो गई। तीन दिन पहले उत्तर प्रदेश के नोएडा के थाना फेस वन क्षेत्र स्थित डी-93 सेक्टर-दो स्थित शाम पेंट इंडस्ट्रीज केमिकल की कंपनी में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि लपेटें आसमान तक खूबी नजर आ गई। करीब ढाई घंटे की मशकत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फायर ब्रिगेड टीम ने इस आग की घटना में किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान न होने की बात कही है। इसी 16 जून को उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव अतरासी से करीब दो किलोमीटर दूर यह फैक्ट्री चार महिलाओं की मौत हो चुकी थी। नौ घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि फैक्ट्री संचालक ने पटाखे बनाने के लिए आसपास की रहने वाली महिलाओं को कम मजदूरी पर रखा था। उन्हें केवल 300 रुपये दिहाड़ी दी जाती थी। मजदूरों को न कभी ट्रेनिंग दिलाई और नही आपातस्थित से निपटने का कोई प्रशिक्षण दिया गया। फैक्ट्री में दुर्घटनाएं होने पर कुछ दिन शोर मचता है। मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा होने के बाद सब शांत हो जाता है। दुर्घटनाएं रोकने की कोई योजना नहीं बनती। नहीं फैक्ट्री के श्रमिकों को दुर्घटना होने के समय की चुनौती बताई जाती है। दुर्घटना होने के समय की चुनौती के समय के लिए प्रशिक्षण भी नहीं किया जाता। दुर्घटना होने पर क्या किया जाए इसका भी प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। फैक्ट्री लगती है किंतु उनका तकनीकि निरीक्षण नहीं होता। निरीक्षण करने वाली अधिकारी पैसे के बल पर अपने आफिस में ही बैठकर रिपोर्ट बना देते है। सही मायने में फैक्ट्रियों में होने वाली दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौत का जिम्मेदार वह अमला भी है जो समय-समय पर इनके सुरक्षा तंत्र का निरीक्षण करता है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के महानिदेशालय फैक्ट्री सलाह सेवा और श्रम संरक्षान द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत के पंजीकृत फैक्ट्रियों में दुर्घटनाओं के कारण हर दिन औसतन तीन मजदूरों की मौत हुई है और

11 घायल होते हैं।नवंबर 2022 में आरटीआई जवाब के अनुसार, भारत में रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों में हर साल होने वाली दुर्घटनाओं में 1,109 वर्कर्स की मौत हो गई और चार हजार से अधिक वर्कर घायल हुए। ये 2017 से 2020 के बीच आंकड़ों के आधार पर है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि यह संख्या और भी ज्यादा है क्योंकि बड़े पैमाने पर असंगठित क्षेत्रों में होने वाले हादसों की रिपोर्ट दर्ज ही नहीं की जाती है।

निदेशालय जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट्स की रिपोर्ट, 2022 के अनुसार 2021 में, महाराष्ट्र में 6,492 खतरनाक फैक्ट्रियों में से केवल 1,551 का निरीक्षण किया गया, जिससे 23.89 प्रतिशत निरीक्षण दर प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त, 39,255 पं-जीकृत फैक्ट्रियों में से केवल 3,158 का निरीक्षण किया गया। इससे 8.04 प्रतिशत निरीक्षण मिली। अन्य प्रमुख औद्योगिक राज्यों में भी यह प्रवृत्ति दिखाई देती है। तमिलनाडु में सामान्य निरीक्षण दर 17.0 प्रतिशत और खतरनाक फैक्ट्रियों की निरीक्षण दर 25.39 प्रतिशत थी। गुजरात में सामान्य निरीक्षण दर 19.33 प्रतिशत और खतरनाक फैक्ट्रियों की निरीक्षण दर 19.81 मिली।। 2021 के लिए अखिल भारतीय आंकड़े सामान्य निरीक्षणों के लिए 14.65 प्रतिशत और खतरनाक फैक्ट्रियों के लिए 26.02 प्रतिशत थे। उपर्युक्त विवरण से लिया गया है। खराब निरीक्षण दरों का एक कारण कर्मचारियों की कमी है। महाराष्ट्र में निरीक्षकों की नियुक्ति दर केवल 39.34 प्रतिशत थी। इसमें 122 स्वीकृत अधिकारियों में से केवल 48 कार्यरत थे। गुजरात में नियुक्ति दर 50.91 प्रतिशत रही, तो तमिलनाडु में यह 53.57 प्रतिशत थी। अखिल भारतीय नियुक्ति दर 67.58 प्रतिशत थी। स्वीकृत पदों की संख्या पंजीकृत फैक्ट्रियों की



संख्या के सापेक्ष वार्षिक निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त रही है। 2021 में, अखिल भारतीय स्तर पर 953 स्वीकृत निरीक्षकों में से प्रत्येक को वार्षिक रूप से 337 पं-जीकृत फैक्ट्रियों का निरीक्षण करना पड़ता है। मई 2024 में, महाराष्ट्र इंडस्ट्री डेवलपमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने एक मीडिया रिपोर्ट में स्वीकार किया कि सुरक्षा निरीक्षण और प्रमाणन अक्सर ऑडिटर्स और फैक्ट्री मालिकों या प्रबंधकों के बीच रसमझरे के आधार पर किए जाते थे। यह संकेत देता है कि नियोक्ता भी श्रम निरीक्षकों के समान ही दोषी हैं, और प्रष्ट प्रथाओं की र्आपूर्ति पक्षर को संबोधित करना र्हमांगर पक्ष के सुधार के समान ही महत्वपूर्ण है। प्रदेश स्तर पर विशिष्ट सीमा मात्रा के साथ खतरनाक रसायनों और ज्वलनशील गैसों की एक सूची स्थापित की जानी चाहिए।प्रत्येक राज्य

को प्रमुख खतरे वाले कार्यस्थलों की सूची बनाए रखनी चाहिए। समें सुविधा का प्रकार, उपयोग किए गए रसायन और संग्रहीत मात्रा का विवरण हो। खतरनाक सामग्री की सूची और इन्चेंट्री को एक केंद्रीकृत डेटाबेस में संग्रहीत करें, जिस तक निचामक निकाय, आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ता, और जनता आसानी से पहुंच सकें। निरीक्षण प्रणाली को उदार बनाने के बजाय, सरकारों को आईएलओ सम्मेलन के प्रावधानों का पालन करके मजबूत श्रम बाजार शासन सुनिश्चित करना होगा। प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति और खतरनाक और रासायनिक पदार्थों के उपयोग को देखते हुए, सख्त निरीक्षणों की आवश्यकता है। औद्योगिक आपदाओं की पुनरावृत्ति सरकार की विफलता को दर्शाती है कि उसने पिछले घटनाओं से सबक नहीं सीखा है। सुधारों और कमजोर शासन के नाम पर, राज्य अपने मूल कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता कि वह एक सुरक्षित कार्य और जीवन सुनिश्चित करे। एक प्रभावी और नैतिक श्रम निरीक्षण प्रणाली

सुनिश्चित करने के लिए सार्थक सुधारों की आवश्यकता है जो श्रमिकों और समुदाय की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता दें। इसके साथ ही फैक्ट्री श्रमिकों का आपदा के समय सुरक्षा के उपाय, कैसे बचाव करें आदि का बार-बार प्रशिक्षण देना होगा। सभी उद्योगों के निरीक्षण के लिए तकनीकि विशेषज्ञों की टीम बनानी होगी। उन्हें नियमित निरीक्षण के निर्देश करने होंगे। इससे किसी दुर्घटना होने पर मौत और घायलों का आंकड़ा कम किया जा सकता है। दुर्घटना होने के हालात में इन तकनीकी अधिकारियों की जिम्मेदारी भी फिक्स करनी होगी। देखने में आ रहा है कि निरीक्षण स्टाफ को फैक्ट्री स्वामियों से मिलीभगत होने के कारण उद्योग स्वामी प्रायः प्रशिक्षित स्टाफ नहीं रखते। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के अगवानपुर की दुर्घटना ग्रस्त पटाखा फैक्ट्री का भी ये ही कारण रहा। फैक्ट्री स्वामी ने सस्ते के चक्कर में फैक्ट्री के आसपास रहने वाली महिलाएं रख रखी थी। उन्हें वह मात्र तीन सौ रूपया रोज मजदूरी देता था। उनकी सामाजिक सुरक्षा आदि का भी प्रबंध नहीं था।

केंद्र ही नहीं प्रदेश सरकारों को भी उद्योग स्वामियों को बताना होगा कि उनके यहां काम करने वाले श्रमिक और तकनीकि विशेषज्ञ देश की धरोहर है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उद्योग के साथ देश और समाज की भी है। घटना होने पर मात्र जांच के आदेश और मुआवजा देने से ही काम नहीं चलेगा। दुर्घटना के लिए जिम्मेदारी भी तै करनी होगी। जिम्मेदार लोगों को दंडित भी करना होगा तभी जाकर ये दुर्घटनाएं रूकेगी। एक बात और यदि उद्योग में सुरक्षा मानक कड़े हों, उद्योग श्रमिकों को समय-समय पर सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण मिले तो दुर्घटनाएं ही न हों। हों तो मौत और घायलों की संख्या बहुत कम रहे। दुर्घटनाएं न हो तो उद्योग भी न मरे। दुर्घटनाएं होने से श्रमिकों के साथ एक प्रकार से संबंधित उद्योग भी मर जाता है। अधिकतर दुर्घटनाग्रस्त उद्योग के स्वामी दुर्घटना के कारण हुए नुकसान, श्रमिकों को मुआवजा आदि देने के कारण बर्बाद हो जाते हैं। वे दुबारा से मुश्किल से ही काम को जोड़ पाते हैं। इससे देश का एक व्यापारी, एक व्यवसायी भी एक प्रकार से मर जाता है। उसका आर्थिक रूप से मरना देश की प्रगति को भी नुकसान देता है।

फियादीन हमले की 20वीं बरसी : रामपथ व रामजन्म भूमि परिसर की बढ़ी निगरानी

अयोध्या। राम मंदिर पर फिदायीन हमले की 20वीं बरसी के मद्देनजर परिसर की सुरक्षा में सख्ती बरतते हुए परिसर के चप्पे-चप्पे की निगरानी बढ़ा दी गई है। रामपथ व रामजन्मभूमि परिसर के चारों ओर आने-जाने वाले सभी वाहनों की गत शुक्रवार की शाम सघन जांच अभियान शुरू होने के साथ ही अनावश्यक रूप से परिसर के आसपास घूम रहे लोगों से पूछताछ की गई। इस दौरान उनके परिचय पत्रों की गहनतापूर्वक पड़ताल की गई।

बताते चलें कि एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे ने रामजन्मभूमि चौकी प्रभारी सुनील कुमार व कमांडो दस्ते के साथ रामजन्मभूमि परिसर का निरीक्षण कर चेकिंग व्यवस्था का मुआयना किया और तैनात सुर-क्षाकर्मियों को पूरी सजगता से ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए। उन्होंने रामकोट, राम गुलेला, रामजन्मभूमि पथ, यात्री सेवा केंद्र, अंगद टीला व वीवीआइपी द्वार सहित अन्य स्थानों पर पहुंच कर यहां की व्यवस्था का निरीक्षण किया और सघन चेकिंग के बाद ही दर्शनार्थियों व अन्य कर्मियों को प्रवेश देने के निर्देश दिए। एसपी बलरामाचारी दुबे ने कहा कि प्रत्येक स्थलों

पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वाच टावर से निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दिए।

बाल रामाचारी दुबे ने बताया कि राम मंदिर में सीआरपीएफ, एसएसएफ, पीएसी के साथ स्थानीय पुलिस तैनात है। राम मंदिर के आसपास एक हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जहां 24 घंटे मॉनिटरिंग भी की जाती है। एंटी ड्रोन सिस्टम को भी लागू कर दिया गया है। अभी हम उस दिन को नहीं भूल पाए कि आज से 20 वर्ष पहले यानी 5 जुलाई 2005 को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि परिसर की बैरकेटिंग के पास तेज धमाका होता है। इस धमाके से कुछ दूर की बैरकेटिंग का जाल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। आतंकियों की योजना अयोध्या में बने प्रभु राम के अस्थाई मंदिर को रॉकेट लांचर और ग्रेनाइड से उड़ाने की थी। आतंकियों ने गोलीयां चलायी भी शुरू कर दी थी, दो आतंकी का मकसद प्रभु राम के टेंट को उड़ाना था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने पांचों आतंकियों को मार गिराया था। 20 वर्ष बाद अयोध्या की तस्वीर पूरी तरह से बदलती नजर आ रही है। राम मंदिर पर हमले की यह घटना आतंकियों की दुर्भावना-

► मॉनीटरिंग के लिए

राम मंदिर के आसपास एक हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ एंटी ड्रोन सिस्टम भी लागू



दुस्साहस, रामजन्मभूमि परिसर में तैनात सुरक्षाकर्मियों के असाधारण शौर्य और सबसे बढ़कर रामलला की महिमा-गरिमा के लिए जानी जाती है। उस हमले की आपदा का सामना कर चुकी पीढ़ी के लिए उसकी स्मृतियां आज भी जीवंत हैं। कृष्णचंद्र सिंह ने हमले का सामना बहुत निकट से किया और उनसे इस हमले का अनुभव साझा करना रोचक तथा हमले से जुड़ी धारणाओं को प्रामाणिकता प्रदान करना है। कृष्णचंद्र सिंह उस समय परिसर की सुरक्षा में लगी

पीएसी की 11वीं बटालियन के कंपनी कमांडर थे। जब आतंकियों ने जीप ब्लास्ट से पूर्वोत्तर की बैरीके-डिंग उड़ा कर परिसर में प्रवेश किया, तब वह अपने ड्यूटी प्वाइंट से कोई सौ मीटर दूर चाय पी रहे थे। ब्लास्ट की आवाज से वह पहले ही असहज हो चले थे, तभी जीप के बरहवास ड्राइवर ने बताया कि आतंकियों ने उसकी जीप छीन कर ब्लास्ट कर दी और मंदिर परिसर में प्रवेश किया है। कृष्णचंद्र सिंह चार-पांच पीएसी के जवानों के साथ आतंकियों की

दिशा में भागे। आतंकियों के पास सौ से अधिक ग्रेनेड, राकेट लांचर, पिस्टल और एंके 47 जैसे अत्याधुनिक अस्त्रलह थे। जवाबी कार्रवाई के लिए रिवाल्वर व जवानों की एसएलआर थी। दस बजते-बजते हमारी टीम ने तीन आतंकियों को गोलियों की बौछार से ढेर कर दिया। पीएसी के जवानों की एसएलआर ने एक बार पुनः सघन प्रवाह के साथ आग उगली और इस तरह सभी पांच आतंकियों की कहानी रामलला के पास फटकने से पहले ही समाप्त हो गई।

नगर पंचायत रामकोला का होगा सुन्दरीकरण

- **रामकोला में लगेंगी विक्टोरिया लाइटें**
- **मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत नगर पंचायत प्रशासन 37 लाख रुपए**

कुशीनगर, रामकोला। नगर पंचायत रामकोला में विक्टोरिया लाइट लगेगी। मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत नगर पंचायत प्रशासन 37 लाख रुपये खर्च करेगा। शासन से धन स्वीकृत हो गया है, जल्द ही काम शुरू होगा। इससे कस्बे की सुंदरता जहां बढ़ेगी। वहीं नगरवासियों को सहूलियत मिलेगी। तीन माह के अंदर कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रामकोला कस्बे में सड़क के दोनों तरफ लाइट लगाया जाएगा। इसके पूर्व लाली लाइटें खराब हो गई थीं। इसके चलते शाम होते ही बाजार में अंधेरा छा जाता था। सुबह मॉर्निंग वाक पर निकलने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन से इसके लिए कई बार मांग किया।

शासन को इसके लिए नगर प्रशासन से पत्र लिखा था। शासन ने इसकी स्वीकृति देते हुए बजट भी दे दिया है।

नगर अध्यक्ष प्रणिथि सतीश चौधरी ने बताया कि पथ प्रकाश के लिए जोर दिया जा रहा है। शासन में इसके लिए पहल की गई थी। बजट मिल गया है। टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है।

नगर में पडरौना रोड, कप्तानगंज रोड, सिंगहा रोड के दोनों तरफ पथ प्रकाश की व्यवस्था की गई है। नवसुजित मोहल्लों में भी पथ प्रकाश की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए तैयारी चल रही है। ईओ संतोष कुमार वर्मा ने कहा कि पथ प्रकाश के लिए स्वीकृत हुआ है, कार्य शुरू हो गया है जो जल्दी पूरा हो जाएगा।

निकाला गया अलम का जुलूस

बस्ती। पुरानी बस्ती क्षेत्र में बृहस्पतिवार देशराम मुहर्रम कमेटी की तरफ से अलम का जुलूस निकाला गया। मंगल बाजार होकर जुलूस करुआ बाबा के स्थान होते हुए आगे बढ़ा। इस दौरान बड़ी संख्या में फोर्स मौजूद रही। दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र मिश्रा उर्फ पट्टू बाबा, सर्राफ व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष कुंदर वर्मा आदि ने मुहर्रम कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद नसीम सहित उनकी कमेटी के पदाधिकारी का स्वागत व जलपान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भारी फोर्स मौजूद रही।

कांवड़ मेला: दुकानदारों पर लगेगी नाम पट्टिका

बस्ती। कांवड़ यात्रा के दौरान मेल और कांवड़ रूट पर लगने वाली दुकान पर दुकानदार के नाम की पट्टिका लगाई जाएगी। इसके लिए माइक्रो प्लान तैयार किया गया है। एसपी अभिनंदन ने बताया कि सभी को यह जानने का हक है कि वे सामान किससे खरीद रहे हैं। इस संबंध में शासन के निर्देशानुसार प्रबंध कराया जा रहा है। श्रावण मेला और कांवड़ यात्रा को सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने को लेकर बृहस्पतिवार को पुलिस लाईंस सभागार में एसपी ने ने सभी थानेदारों व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें चौकी प्रभारी से लेकर सभी थानाध्यक्षों, ट्रैफिक पुलिस, एलआईयू आदि से फीडबैक लिया गया। सभी को जिसमें शासन व डीजीपी स्तर से जारी किए गए दिशा निर्देशों के बारे में उन्हें अवगत कराया गया। एएसपी ओपी सिंह, सीओ सिटी सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी, सीओ कलवारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी, रघौली सीओ स्वर्णिमा सिंह की मौजूदगी में रूट प्लान पर चर्चा की गई। इसके साथ ही रूट डायवर्जन व्यवस्था, राजस्व विभाग, चिकित्सा विभाग आदि के साथ समन्वय स्थापित करने, पूर्व में श्रावण-कांवड़ यात्रा के दौरान हुई सामने आई कमियों के संबंध में, कांवड़ियों व श्रद्धालुओं के विश्राम करने, गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था, एम्बुलेंस व चिकित्सकीय सुविधा आदि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

परिवहन विभाग का 15 दिवसीय विशेष अभियान शुरू

महाराजगंज। जनपद में स्कूली वाहन के रूप में १32 बसों का पंजीकरण है, बावजूद 100 से अधिक बसें बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के संचालित की जा रही हैं। परिवहन विभाग ने इनके खिलाफ 15 दिन का विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस समय अवधि के बाद भी स्कूल वाहन अगर अनफिट मिलते हैं तो विभाग उन्हें जब्त कर लेगा, जिनकी रिलीजिंग सिर्फ कोर्ट से होगी।परिवहन विभाग ने नया शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने के बाद मई में स्कूली वाहनों को फिटनेस प्रमाणपत्र लेने और नवीनीकरण के निर्देश दिए। स्कूली वाहन के रूप में पंजीकृत कुछ वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र जारी भी किए गए, लेकिन पंजीकृत सभी वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं जारी कराए गए।

देशी शराब ठेका खोले जाने के खिलाफ महिलाओं ने किया प्रदर्शन

► प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय जा रही

महिलाओं को पुलिस ने गुरुधाम चौराहे के निकट रोका

► मय पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे

भेलूपुर एसीपी, भेलुपुर और चितईपुर के थानाध्यक्ष

► विधायक ने दिया समस्या का समाधान करने का आश्वासन



वाराणसी। दुर्गाकुंड क्षेत्र के घसियारी टोला में देशी शराब का ठेका खोले जाने के विरोध में गत दिनों शुरुवार को सैकड़ों की संख्या में स्थानीय महिलाएं प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय जाने के लिए निकलीं लेकिन पुलिस ने सभी को गुरुधाम चौराहे पर ही रोक

दिया। महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि दुकानों को जल्द बंद किया जाए, इससे हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। महिलाएं ठेका खोले जाने के खिलाफ नारेबाजी करने लगीं। उनका कहना है कि इस इलाके में धार्मिक स्थल सहित बच्चों का आवागमन होता है।

निर्माण कार्य के दौरान ईंटों से निकले कोबरा

परिवार के 24 सर्प

कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कसघा ब्लॉक अंतर्गत बटेसरा गांव में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक ही घर से 25 सांप मिलने का मामला प्रकाश में आया है। गांव के निवासी सहीम आलमीन के घर में निर्माण कार्य के दौरान अचानक ईंट और मिट्टी हटते समय एक विशाल कोबरा सांप दिखाई दिया। सांप को देखकर परिवार के लोग दहशत में आ गए और शोर मचाया। मामले की जानकारी सर्प मित्र को दी गई। इसके बाद सांपों को रेस्क्यू किया गया। बड़ी संख्या में सांपों के पाये जाने की सूचना मिलते ही ग्राम प्रधान मोहन लाल गुप्ता ने तुरंत सर्प मित्र शत्रुघ्न यादव को बुलाया। शत्रुघ्न यादव मौके पर पहुंचे और बिना कोई देर किए रेस्क्यू अभियान शुरू किया। जब मिट्टी को धीरे-धीरे हटाया गया, तो वहां एक बड़े कोबरा सांप के साथ उसके 24 छोटे बच्चे भी पाए गए। ये सभी सांप ईंटों के नीचे दबे हुए थे। शत्रुघ्न यादव ने पूरे साहस और सूझ-बूझ के साथ सभी सांपों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला। हालांकि, एक बड़ा सांप ईंटों के नीचे दबकर पहले ही मर चुका था, लेकिन शेष 24 सांपों को जीवित बचा लिया गया। बाद में इन सभी को सुरक्षित रूप से नजदीकी जंगल में छोड़ दिया गया।

गंभीर खतरा बन रहा लेदर में इस्तेमाल किया जाने वाला क्रोमियम
कानपुर। चमड़ा उद्योग से निकलने वाला प्रदूषण कानपुर के लोगों के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है।लेदर में इस्तेमाल क्रोमियम की चपेट में आने वालों की संख्या में और इजाफा हुआ है। 24 जून को शहरी क्षेत्रों के 157 लोगों के खून में भी क्रोमियम तय मानक से अधिक निकला है। शुक्रवार को सेंपल की जारी रिपोर्ट में 20 लोगों में मर्करी (पारा) भी तय मानक से ज्यादा पाया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर 24 जून को स्वास्थ्य विभाग ने रूमा, जाजमऊ व पनकी औद्योगिक क्षेत्र, तेजाब मिल का हाता, राखी मंडी, नौरियाखेड़ा में शिविर लगाया गया था। छह जगह के 177 लोगों का ब्लड सैंपल राममनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ जांच के लिए भेजा गया था। इनमें महिलाएं 102 और पुरुषों की संख्या 75 थी।

सीएमओ के अनुसार, शासन के आदेश पर आगे बढ़ाएंगे कदम सीएमओ डॉ. उदयनाथ ने 24 जून को छह जगह में शिविर लगाकर 177 लोगों के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि राममनोहर लोहिया अस्पताल में जांच के लिए सभी ब्लड सैंपल भेजे गए थे। 157 लोगों में क्रोमियम मानक से अधिक पाया गया है। वहीं 20 लोगों के ब्लड में मर्करी भी तय मानक से अधिक मिला है। अब इन इलाकों को लेकर क्या योजनाएं बननी हैं, इसको लेकर शासन के आदेश का इंतजार है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है।

ब्लड में क्रोमियम या मर्करी स्तर से अधिक होना खतरनाक है। इससे शरीर के तमाम अहम अंगों के पूरी तरह खराब होने व गंभीर रोगों की चपेट में आने की आशंका काफी बढ़ जाती है।

वीपी प्रियदर्शी, विभागाध्यक्ष जीएसवीएम



रिलायंस की पहल: शीतल पेय बाजार को मुद्दी में समेटने की कोशिश

एक खामोशी... जबकि शीतल पेय जल बाजार में तो झगमगे में सनसनी में ही ज्यादा भरोसा करता है। उसके बिना न तो चार पैसे की चीज पन्द्रह और बीस रुपए में बेची जा सकती है, न एक गैर-जरूरी और एक हद तक नुकसानदेह पेय को हम-आप शान से पी सकते हैं। इसी के सहारे दो बड़ी कंपनियां हजारों करोड़ का कारोबार कर चुकी हैं और सारे देसी ब्रांड लगभग समाप्त कर चुकी हैं। शीतल पेय गांव-देहात में मिलाता है। फैशन की चीज बन गया है पर इस बार की शांति एक और कारण से ज्यादा चुभने वाली है। इस बार शीतल-पेय बाजार में एक नया खिलाड़ी उतरा है जिसने दमदार दखल दी है। बाजार में आने के साथ ही उसने एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। स्थापित ब्रांडों को झकझोरा है, वितरकों को निहाल कर दिया है। ग्राहक भी पुरानी कीमत में पेय की मात्रा लगभग दोगुनी पाकर खुश है लग रहा है विदेश का शीतल पेय बाजार बदलने जा रहा है। दशकों पहले मर गये ब्रांड, कैम्पा कोला' को 'पार्ले ड्रिंक्स' से मामूली

किसी के बिना दिल न लगे उसे मोहब्बत कहते हैं
कननाल, हरियाणा। धूमधाम से मनाया, कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ शायर डॉ एस के शर्मा ने की, मुख्य अतिथि लेखिका व कवयित्री रेशमा कल्याण रही, विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजसेवी रचना गुप्ता,कवि दलीप खरेरा, समाजसेवी प्रेम धीमान रहे, विशेष अतिथि कवयित्री व समाजसेवी पूनम गोयल,एम डी डी बाल भवन संस्थापक पी आर नाथ व अध्यक्ष परमिंदर पाल सिंह रहे। मंच संस्थापक रामेश्वर देव व मंच सदस्यों ने सभी का स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से कुमारी खुशबू ने की, कार्यक्रम अध्यक्ष वरिष्ठ शायर डॉ एस के शर्मा ने कहा तेरे दीदार की हसरत है मुझको,बस आंखों का उजाला चाहता हूं,मुख्य अतिथि लेखिका व कवयित्री रेशमा कल्याण ने कहा सफर करते हैं मुसलसल सोच कहीं तो पहुंचेंगे,मंजिल पर ना सही मुकाम तक तो पहुंचेंगे,विशिष्ट अतिथि रचना गोयल ने कहा कौन कितना निष्ठावान है, लोग भावों से पहचान लेते हैं, कवि दलीप खरेरा ने कहा बीन बजता नाच नचता आन सधी ने उसकी चंरा, साँपों की इस बस्ती में आ गया है आज सपेरा,समाजसेवी प्रेम धीमान ने कहा प्रेम ना होता तो कुछ भी ना होता,जागता ना कोई ना कोई सोता,विशेष अतिथि कवयित्री पूनम गोयल ने कहा कि-सी से दिल लग जाए उसे मोहब्बत थोड़ी कहते हैं, किसी के बिना दिल न लगे उसे मोहब्बत कहते हैं,शायर व मंच संचालक गुलजार जिगर देवबंदी ने कहा हम सफर मेरा अगर वो गुलबदन हो जाएगा, फिर तो मेरे घर के आँगन का चमन हो जाएगा, कवयित्री सीमा रंगा इंद्रा ने कहा देश के बेटों के संग बेटियों ने भी कमान संभाली है,देश की सुरक्षा के लिए दोनों की बात निराली है,मंच संस्थापक रामेश्वर देव ने कहा.जिधर से तुम गुजरते हो महक तो आ ही जाती है,तुम्हारी मीठी बातों से चहक तो आ ही जाती है,कवि प्रेम पाल सागर ने कहा वतन के खातिर काम भले का कर जाते तो अच्छा था,डॉ सत्यबीर सिंह निराला ने कहा हुआ है गायब जहां से यारों,कहीं भरोसा नजर न आए,शायर इकबाल पानीपती ने कहा मगरूर तो बहुत था बलाओं का सिलसिला, टूटा न मेरी मां की दुआओं का सिलसिला,डॉ संजय जैन ने कहा कभी मैं नाव कागज की न बारिश में चला पाया, शकुन्तला काजल शकुन ने कहा सरबती आंखें गुलाबी होठ बैरन के चुनो,डॉ अंजु शर्मा ने कहा जाति नहीं कोई वीरों की धर्म नहीं रणधीरों का,शायर सिराज पैकर ने कहा शायदी हुई तो बीवियों के साथ हो गए,एक बुढ़ा बाप रह गया बेटों को पाल के,सुमन मुस्कान ने कहा किस्दार पे वो पहले नजर अपने डाल लें,डॉ सुशील हसरत नरेलवी ने कहा वक्त के सांचों में कैसी कैसी खामी रह गई,मुंमू बदायूनी ने कहा सितारे बन के आसमान में बिखर जाते हैं,अनुपिंदर सिंह अनूप ने कहा टपके घर की छत अगर बरसात में,गायत्री आर्य कौशल ने कहा वो चांद क्या हुआ वो सितारे कहां गए,डॉ उर्वी ऊदल ने कहा मेरे जैसी दिवानी नहीं पाओगे।

क्यों नहीं पहुंच पातीं सरकारें घरों की दहलीज़ तक?

भारतीय राजनीति में महिलाओं के सशक्तीकरण की बातें खूब होती हैं। चुनावी घोषणापत्रों में उनके लिए वादे भी किए जाते हैं, परंतु चुनाव बीतते ही वायदों पर धूल की परत जम जाती है। शायद ही कोई जनप्रतिनिधि उनके दुख-दर्द को सुनने, उनकी अपेक्षाओं को समझने के लिए घर की दहलीज तक जाता हो? यह एक कड़वी सच्चाई है जिसे देश के अधिकांश राज्यों में महिलाओं ने जिया है। लेकिन तारीफ करनी होगी बिहार की जिसने इस परिपाटी को तोड़कर एक नई मिसाल कायम की है। एक ऐसा प्रदेश, जिसने दशकों तक महिलाओं को पुरुषों के निदेशों पर मताधिकार का प्रयोग करते देखा, आज वही महिला सशक्तीकरण की एक ऐसी नई इबारत लिख रहा है, जो देश के लिए एक अनुरकणीय मॉडल बन चुकी है। इस परिवर्तनकारी यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव 'महिला संवाद' कार्यक्रम है, जिसे विगत 18 अप्रैल से प्रदेश में ग्राम स्तर पर शुरू किया गया। यह पहल केवल एक सरकारी कवायद नहीं, बल्कि महिलाओं को केंद्र में रखकर सामाजिक बदलाव को फिट देने का एक सशक्त माध्यम है। यह कार्यक्रम प्रदेश की बेटियों, माताओं और बहनों की आवाज को गंभीरता से सुनने, समझने और भविष्य की नीतिगत व प्रशासनिक पहलों को आकार देने का एक महत्त्वपूर्ण मंच बन गया है।

यह संतोष का विषय है कि अब तक 38 जिलों में 52,468 महिला संवाद कार्यक्रमों का सफल आयोजन हो चुका है, जिसमें कुल 1 करोड़ 13 लाख से अधिक महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। यह संख्या इस बात का भी जीवंत प्रमाण है कि प्रदेश की महिलाएं आगे बढ़ती आवाज उठाते और सरकार से सीधे जुड़ने को लेकर कितनी उत्सुक और जागरूक हैं। दरभंगा से लेकर पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्णिया, समस्तीपुर, नालंदा और वैशाली तक, हर जगह महिलाओं ने बेबाकी से अपनी बात रखी है। उन्होंने नीति-निमाताओं को यह समझने का अवसर दिया है कि महिला सशक्तीकरण की दिशा में आगे किन प्राथमिकताओं के साथ कदम बढ़ाए जाएं।

महिला संवाद की यह पृष्ठभूमि आकस्मिक नहीं है। नीतीश कुमार के कार्यकाल को ध्यान से देखें तो पता चलाते है कि सबसे पहले, लड़कियों में शिक्षा की अलख जगाने पर जोर दिया गया। जहां वर्ष 2000 के आसपास बिहार में लड़कियाँ सरकारी स्कूलों में कम जाती थीं, वहीं वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना की शुरुआत ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। इस योजना ने लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया, जिससे वे दूर-दराज के गांवों से भी साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचने लगीं। इसकी सफलता ने देश के अन्य राज्यों को भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा के साथ-साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी नौकरियों में भी ऐतिहासिक कदम उठाए गए। वर्ष 2013 से पुलिस भर्ती में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। 2016 से सभी प्रकार की सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया जा रहा है, और प्राथमिक शिक्षक नियोजन में तो 50 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें सशक्त किया गया है।

महिलाओं के सशक्तीकरण और गरीबी उन्मूलन में 'जीविका' स्वयं सहायता समूह का गठन भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से ऋण लेकर शुरू की गई 'जीविका' ने ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक उन्नति के लिए परदान साबित हुई है। मुख्यमंत्री द्वारा इन महिलाओं को दिया गया 'जीविका दीदी' नाम आज एक पहचान बन चुका है। वर्तमान में, बिहार में 10 लाख 64 हजार स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, जिनसे 1 करोड़ 35 लाख से अधिक

कीमत पर खरीदकर मुकेश अंबानी और रिलायंस ने एक नए कारोबार में कदम बढ़ाए हैं और वहां के सारे समीकरण बदल दिए हैं। प्रतिद्वंदी ब्रांडों ने कीमत कम की है। मात्रा बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ग्राहक और नीचे तक के वितरक दूसरे ब्रांड से पट जाएं तो काम आसान नहीं रहता। पेप्सी और कोक की तरफ से अभी जवाबी हमला नहीं हुआ लेकिन बाजार तो बदलता दिखता है। जानकार मानते हैं कि कैम्पा का शेयर दहाई में आ चुका है जिस आईपीएल के प्रसारण में कोक और पेप्सी तथा भारत में बिकने वाले उनके सबसे लोकप्रिय ब्रांड थम्सअप के

नए-नए विज्ञापनों की बाढ़ रहती थी। एक दूसरे को गुलाबजामुन और घंटिया स्वाद वाला बताया जाता था जिस लाल को अपने नीले को दुश्मन बताया जाता था वैसे इस बार कुछ नहीं है। दक्षिण के एक हीरो का बहुत औसत किस्म का विज्ञापन ही बार बार दोहराया जा रहा था और सूचना दे रहा था कि-"कोक-पेप्सी" दौर के पहले



जिप कैम्प का जलवा था वह वापस लौट आया है। पेप्सी ने पार्ले ड्रिंक्स से काफी कुछ खरीदा था लेकिन इन ब्रांडों को मरने के लिए छोड़ दिया था।

इन दिनों शीतल पेय की आक्रामक मंडी थोड़ी ठंडी दिखाई दे रही है। हर साल की तरह भाति-भाति के शीतल पेय बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए बाजारों में नहीं आए हैं जून में कायदे से लू की गर्मी को, लू से मरने वालों की और गर्मी की बीमारियों की चर्चा होनी चाहिए, एसी, कूलर की बिक्री की चर्चा होनी चाहिए। पर हो रही है-आंधी-पूफान-बारिश और जल-जमाव की इसमें भी कम

जाम के झाम से मुक्ति के हों पुख्ता इंतजाम

27 जून को इंदौर-देवास हाईवे पर करीब पर 40 घंटे तक 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसमें 4000 से ज्यादा वाहन फंस गए थे। इस दौरान 3 लोगों की जान चली गई। 14 जून को केरल के कन्नूर में कोट्टियूर के पास एक तीन वर्षीय बच्चे की अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस के भीषण ट्रैफिक जाम में फंस जाने से मौत हो गई। 7 जून दिल्ली से आए एक 62 वर्षीय पर्यटक कमल किशोर टंडन की मसूरी में भीषण ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। 6 मई उउ के हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में एक डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और राजमार्ग पर तीन घंटे तक जाम फंसे रहने की वजह से उसे वक्त पर उचित उपचार नहीं मिला और इस वजह से उसकी मौत हो गई। 24 अप्रैल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मुख्य बाजार देहरा में समय सड़क निर्माण कार्य के कारण लगे भारी जाम ने 75 साल के बुजुर्ग की जिंदगी छीन ली। 24 फरवरी कोटा राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर दरा नील में लगने वाले भीषण जाम ने एक मासूम की जान ले ली। ये तो बानगी भर है। इस तरह की खबरें अक्सर सुनने, पढ़ने और देखने को मिलती हैं। दो चार दिन के हो हल्ले के बाद गाड़ी पुराने ढर्रे पर दौड़ने लगती है।

ताजा प्रकरण इंदौर-देवास हाईवे पर 40 घंटे के जाम का है। 40 घंटे का जाम था...कोई सोच भी नहीं सकता कि आजादी के 75 साल बाद, 40 किलोमीटर का रास्ता तय करने में 40 घंटे लग सकते हैं। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने में आमतौर पर 16 से 20 घंटे लगते हैं। मतलब जितने में दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ्लाइट का आना जाना हो जाए, उतने में इंदौर से देवास नहीं पहुंच सके। इंदौर से देवास तक का रास्ता महज 40 किलोमीटर है।

मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए नेशनल हाईवे अर्थांरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई को इस घटना के लिए जिम्मेदार बताया था। निश्चित रूप से इस दुर्घटना और हजारों लोगों के घंटों जाम में फंसे रहने के मामले में जहां एनएचएआई की तरफ से माफी मांगने की जरूरत थी, वहीं उसने दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिये दोष लोगों पर लगाते हुए अस्-विदेनशील बयान दे डाला। 30 जून को अदालत में जवाब देते हुए एनएचएआई के वकील ने कहा कि हल्लोग बिना जरूरी काम के इतनी सुबह घर से बाहर निकलते ही क्यों? एनएचएआई की इस टिप्पणी ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया।

उनके इस बयान को सुनकर लोगों को ऐसा लग रहा है कि एनएचएआई घटना की जिम्मेदारी लेने से बच रहा है और घटना के लिए आम लोगों को ही दोषी बताने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी एनएचएआई के रुख को कठोर और संवेदनहीन बताया

है, जो जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करने वाला है। विवाद बढ़ने पर एनएचएआई ने कहा कि,यह टिप्पणी अर्थांरिटी के आधिकारिक विचारों को नहीं दर्शाती।

देश में जहां एक तरफ ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए सड़कों, हाई-वेज और एक्सप्रेस-वेज को बनाने का काम जोरों-शोरों पर चल रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे शहर भी हैं, जो अंदरूनी ट्रैफिक से काफी ज्यादा परेशान हैं। असल में, ट्रैफिक जाम की समस्या से बड़े ही नहीं बल्कि छोटे शहर भी जूझते हैं। लेकिन बड़े शहरों में यह एक संकट का रूप लेने लगा है।



एक जानकारी के मुताबिक एक घंटे जाम में एक लीटर ईंधन बर्बाद होता है। जितनी ईंधन की खपत होगी, उतना ही ज्यादा सीओटू उत्सर्जन भी होगा, जो पर्यावरण और प्रदूषण के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदायक होता है। एक अनुमान के अनुसार, महानगरों में और हाईवे पर देश में हर साल लगने वाले ट्रैफिक जाम से हर साल तकरीबन 1.4 लाख करोड़ रुपये तक का नुकसान हो रहा है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024 के अनुसार, देश में कोलकाता का ट्रैफिक सबसे धीमा है। बेंगलुरु ने इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जगह बनाई है। कमोबेश ऐसे हालात दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, चंडीगढ़, गुरुग्राम, लखनऊ, जयपुर, कानपुर, अमृतसर, अहमदाबाद, वाराणसी और देश के अन्य महानगरों और शहरों के हैं।

डाक्टरों के अनुसार, जाम में फंसने वालों को अकसर ब्लड प्रेशर बढ़ने, बर्नआउट, सांस की बीमारी, डिहाईड्रेशन, फीवर, घबराहट, सीने में दर्द आदि बीमारियों का सामना करना पड़ता है। गंभीर मरीज लंबे समय तक जाम में फंस जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

चर्चा है गर्मी में सर्दी के नाम पर आग लगाने वाले कोल्ड-ड्रिंक कंपनियों की लड़ाई की। गर्मी के साथ आईपीए (इंडियन प्रीमियर लीग) का सीजन भी बीत गया और जिस क्रिकेट और आईपीएल का बहाना बनाकर पेप्सी और कोक महाभारत सी जंग लड़ा करते थे। विपणन और विज्ञापन जगत अपनी इस प्रतिभा को इस सीजन के लिए बचा कर रखता था। वह सब अब इस सीजन में कहीं नहीं दिखा। पुराने मालिक बिसलेरी में ऐसे लग गए कि इन ब्रांडों को सचमुच भूल गए। उनका कोक-पेप्सी को लड़ाई में गुंजाइश नहीं लगी। अब रिलायंस ने नए क्षेत्र में उतरने के इस पुराने ब्रांड पर दांव लगाया है। जानकार मानते हैं कि रिलायंस बड़े स्तर के व्यापार, ग्राहक और वितरक को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने की रणनीति से धमका रहा है। फिलहाल सांसदों और सरकार के सहारे कायदे-कानून बदलवाना, बाजार और विज्ञापन जगत में मारकाट की पेप्सी और कोक वाली रणनीति उसने नहीं अपनाई है। अपने पांव जमाने के लिए सरकार

पर दबाव बनाने तथा बड़ी संख्या में सांसद जुटाकर अपना कानून वाने वाली पेप्सी के लिए यह भी कहा जाता है कि उसने आयात के बदले तीन निर्यात वाला प्रलोभन दांव भी धोखे वाला खेल और जाने किस प्रभाव में समाजवादी कहलाने वाले मंत्री शरद यादव ने उस करार पर दस्तखत कर दिए। उस करार में यह नहीं लिखा था कि- शीतल पेय का कंसंट्रेट जितनी मात्रा में आयात होगा, निर्यात को थोड़े ज्यादा पैसे देवर उनके बासमती, चाय झींगा, मसाले और इसी तरह की चीजों की खेप पर मोहर लगाकर अपने निर्यात का कोटा पूरा किया। उसने एक पैसे का शीतल पेय निर्यात नहीं किया। कानून बदलते ही कोक भी धाया गया तथा स्वदेशी की ठेकेदारी करने वाले रमेश चौहान ने एक मोटा पैसा लिया और ज्यादातर धंधों से हाथ खींच लिया। उसके बाद काफी कुछ हुआ लेकिन एक अजीब बात हुई कि-थम्स अप बाजार का लीडर बना रखा यह एक अर्थ में शीतल पेय बाजार में देसी स्वाद के बने रहने का प्रमाण था।

यदि अब जाम में एंबुलेंस फंसी तो इसे अपराध माना जाएगा और मरीज को नुकसान पहुंचाने के तहत कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके स्थिति में कोई खास फर्क दिखाई नहीं देता। इसमें दो यार नहीं कि सड़कों के नेटवर्क सुधार से उपभोक्ताओं के समय व धन की बचत हुई है तो उद्योग-व्यापार को भी गति मिली है। लेकिन इससे जुड़ी तमाम विसंगतियां भी सामने आई हैं। सड़कों के त्रुटिपूर्ण डिजाइन व निर्माण में चूक को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। वहीं अकसर बड़ी सड़कों और राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण के दौरान अंतहीन असुलिया यात्रियों के लिए रोजमर्रा के अनुभव हैं। अधिकांश साइटों पर निर्माण से जुड़ी, यात्रियों के अनुकूल सर्वोत्तम परंपराओं को अपनाना और यातायात में व्यवधान को कम से कम करना सुनिश्चित नहीं किया जाता है। जानकारों के मुताबिक, जाम की समस्या को खत्म करने के लिए सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना होगा। इसके अलावा लोगों को कार पूलिंग के लिए जागरूक करना होगा जिससे सड़क पर वाहनों की संख्या को कम किया जा सके। सड़क पर जाम का एक बड़ा कारण जगह-जगह कट का होना भी है। पैदल और छोटे वाहनों के आवागमन के लिए मुख्य सड़कों के साथ सर्विस रोड बनाए जाने से भी जाम की समस्या से निजात पाया जा सकता है। जिन स्थानों पर घनी आबादी के चलते सर्विस रोड नहीं बनाए जा सकते। वहां एलिवेटेड रोड, अंडरपास और फ्लाईओवर आदि का निर्माण किया जा सकता है।

जाम से जूझते शहरों में सड़कों की भीड़भाड़ कम करने के लिए केंद्र सरकार सरकार ने राज्यों की राजधानियों समेत दस लाख से अधिक आबादी वाले 94 शहरों में जाम की समस्या के स्थायी समाधान के लिए रिंग रोड, बाईपास समेत अन्य उपाय करने की योजना बनाई है। यूपी में लोगों को जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए पुलों, रिंग रोड और बाईपास का जाल बिछाया जाएगा। इनके निर्माण पर लोक निर्माण विभाग वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 6124 करोड़ रुपए का बजट खर्च करेगा। सीएम योगी के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी की ओर से यह खाका खींचा गया है। निस्संदेह, देश के शहरों में आए दिन जाम लगाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। शासन-प्रशासन को इसके तार्किक समाधान की दिशा में वैज्ञानिक तरीके से गंभीरता के साथ प्रयास करने चाहिए। जाम की सूचना मिलने पर उसे खुलवाने की तत्काल पहल होनी चाहिए। यात्रियों के लिये तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। निश्चय ही, इंदौर-देवास हाईवे की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसको लेकर शासन-प्रशासन के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई को गंभीरता से लेना चाहिए। उन तमाम आशंकाओं को टालना चाहिए जो भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति के कारक बन सकते हैं।

जल राजनीति का राष्ट्रीय सुरक्षा गणना में प्रवेश

भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित कर फिलहाल तकनीकी रूप से नदी प्रवाह, को नहीं काटा है ताकि वैश्विक प्रतिक्रिया न भड़के लेकिन मानसून में नदी के प्रवाह और बाढ़ से संबंधित चेतावनियां साझा करना बंद कर दिया है, जिससे पाकिस्तान का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएआर) असहाय हो गया है क्योंकि पाकिस्तान में बाढ़ संबंधी 90 फीसदी प्रारंभिक चेतावनियां हैं जो भारत से उभे प्राप्त होती हैं। भारत ने जल संग्रह करने का खाका तैयार किया है जिससे आगामी समय में निश्चित रूप से पानी से संबंधित परेशानियां होंगी। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान संधि बहाली के लिए विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र में गुहार लगा रहा है, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस पर तब तक कोई बात नहीं होगी, जब तक कि पाकिस्तान की धरती से पैदा होने वाले आतंकवाद पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई जल संधि ने नदी प्रणाली का 80 फीसदी पानी पाकिस्तान को आवंटित किया था जिसमें सिंधु डेल्टा और चिनाब नदियां शामिल हैं जबकि भारत ने रावी, व्यास और सतलुज पर अपना नियंत्रण बनाए रखा उदारता की वजह से भारत ने अपना नुकसान भी सहा लेकिन अब पानी सिर से काफी ऊपर जा चुका है। भारत ने सुनियोजित रूप से जल प्रवाह में व्यवधान पैदा कर पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था की कमजोरी उजागर कर दिया है। यह संकट न केवल पाकिस्तान की खाद्य और जल सुरक्षा की कमजोरी को सामने लाता है बल्कि इस्लामाबाद द्वारा घोषित आतंकी ढांचे को भी समूल नष्ट करने की तत्काल जरूरत पर बल देता है। अगर पाकिस्तान को अब पानी चाहिए तो उसे न केवल अपनी कश्मीर की रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा बल्कि उसकी धरती पर पनपने वाले आतंकी ढांचे को भी समूल नष्ट करना होगा क्योंकि भारत का संदेश स्पष्ट है कि-टेरर और ट्रेटी अब साथ-साथ नहीं चल सकते हैं।

अनुमानतः सिंधु जल संधि (1960) रह होने से पाकिस्तान में भारी जल संकट पैदा हो जाएगा। पाकिस्तान के पंजाब और सिंधु नदी के पानी पर निर्भर रहने वाले शांत हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रीय खाद्य मंत्रालय के अनुसार, खरीफ सीजन (अप्रैल-जुलाई) में पाकिस्तान के वार्षिक फसल उत्पादन का लगभग 65 फीसदी हिस्सा होता है और खरीफ की लगभग 25 फीसदी बुवाई सिंधु- फेड नहरों पर, सिंचाई पर निर्भर है। पंजाब (जो पाकिस्तान के गेहूं उत्पादन में 70 प्रतिशत से अधिक और गन्ना उत्पादन में 50 प्रतिशत का योगदान देता है) में नहर में पानी की उपलब्धता कम होने के कारण धान और कपास की बुवाई से पहले ही तीन से चार सप्ताह की देरी हो चुकी है।

सिंधु नदी, प्रणाली की प्राधिकरण (आईआरएसए) के अनुसार- सिंध, जहां गन्ना, कपास और धान की खेती प्रमुखता से होती है। वहां सिंचाई जल की उपलब्धता में 30 प्रतिशत की गिरावट आई है। मई के शुरूआत में उपग्रह से प्राप्त चित्रों और एनडीवीआई (सामान्यीकृत अंतर वनस्पति सूचकांक) के रेखान दर्शाते हैं कि पिछले वर्ष की औसत की तुलना में फसल की सघनता में 14 फीसदी की कमी आई है। ओकरा, मुल्तान, बहावलपुर, नकोबाबाद और लरकाना के किसानों ने फसल की खराब स्थिति, मुझ्राते पौधों और भू-जल में कमी का हवाला देते हुए विरोध प्रदर्शन किया है क्योंकि नदी के रिसाव से पुनर्भरण की कमी के कारण ट्यूबवेल सूख गए हैं।

इस्माइल सेरागेलेकर जब विश्व बैंक के उपाध्यक्ष थे, तब उन्होंने 1995 में चेतावनी दी थी कि अगली सदी में युद्ध पानी को लेकर होंगे उस समय कई लोगों ने उसकी इस कन को भय पैदा करने वाला बताकर खारिज कर दिया था। लेकिन दोन दशक बाद उनके शब्द एशिया की अस्थिर सीमाओं पर स्पष्ट रूप से गुंज रहे हैं। जैसे-नदियां सूख रही हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जल संख्या बढ़ रही है। पानी एक साझा संसाधन से भयानक रूप से विवादित भूराजनीतिक हथियार में बदल गया है।

ऐसी ही एक भविष्यवाणी संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बुररस घाली ने की थी कि - पानी 21 वीं सदी में संघर्ष का मुख्य केन्द्र होगा- विशेषकर शुष्क और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में। यह भविष्यवाणी अब दक्षिण एशिया को मूर्त रूप लेती दिख रही है जहां परमाणु हथियार संपन्न देश पड़ोसी भारत, पाकिस्तान और चीन नदी प्रणाली के असजख सह-अस्तित्व में बंधे हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की प्रतिकूल महत्वाकांक्षाओं से लेकर भारत द्वारा सिंधु जल संधि का पुनर्मुल्यांकन करने और हमले के बाद इसे निलंबित करने तक तथा पाकिस्तान के सूखे खेतों और फसलों को नुकसान के बढ़ते डर तक जल- राजनीति राष्ट्रीय सुरक्षा गणना में भी प्रवेश कर चुकी है।

फिकेजरीवाल को दिल्ली के मैदान पर उतरना पड़ा। जबकि दिल्ली में शिकस्त के बाद उन्होंने पंजाब में डेरा डाल दिया था। इस बीच कुछ घटनाएँ भी हुईं। लेकिन वे दिल्ली आने से बचे। इससे लोग कयास लगाने लगे हैं कि शायद वो गम्भीरता पूर्वक दिल्ली में वापस आने का रास्ता और मुद्दे दोनों तलाश रहे थे, जो दिल्ली का अवैध झुगियाँ पर चले बलडोजर ने उन्हें दे दिया।

बेटियों के लिये मोह बढ़ना संतुलित समाज का आधार

दुनियाभर में माता-पिता आमतौर पर अब तक बेटियों की तुलना में बेटों को ज्यादा पसंद करते आ रहे हैं, लेकिन प्राथमिकताओं को लेकर वैश्विक दृष्टिकोण में एक सूक्ष्म, महत्वपूर्ण और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि अब लड़के की तुलना में लड़कियों को अधिक पसंद किया जाने लगा है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि लड़कियों के प्रति पूर्वाग्रह कम है और संभवतः लड़कों के प्रति पूर्वाग्रह ज्यादा है। नए साक्ष्य एवं अध्ययन इस बदलाव का संकेत देते हैं, जो संभवतः बढ़ते एकल परिवार परम्परा, तथाकथित आधुनिक-सुविधावादी जीवनशैली एवं कैरियर से जुड़ी प्राथमिकताओं के चलते लड़कों से जुड़े एक सूक्ष्म भय, उपेक्षा एवं उदासीनता को उजागर करते हैं। ह्राद इकोनॉमिस्ट्स द्वारा ताजा प्रकाशित रिपोर्टों में, लिंग प्राथमिकताओं को लेकर वैश्विक दृष्टिकोण में कुछ ऐसे ही दिलचस्प रुझान सामने आए हैं, जिसमें लड़कों के प्रति सदियों पुराना झुकाव अब कम हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाभर में माता-पिता अब लड़कों की तुलना में लड़कियों को भविष्य की सुरक्षा को लेकर अधिक पसंद कर रहे हैं। विकासशील देशों में, लड़कों के प्रति पूर्वाग्रह कम हो रहा है, जबकि अमीर देशों में लड़कियों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, युवा पुरुषों और महिलाओं के बीच लैंगिक भूमिकाओं को लेकर विचारों में अंतर बढ़ता जा रहा है।

ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में, भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में दो स्थान नीचे है, और इसका लैंगिक समानता स्कोर 64.1 प्रतिशत है। वर्तमान प्रगति की दर से, पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने में 134 वर्ष लगेंगे, जो दशाता है कि प्रगति की समग्र दर धीमी है। इन रिपोर्टों से पता चलता है कि दुनिया भर में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत के लिये लैंगिक समानता की दिशा में दो पायदान की गिरावट का सबसे बड़ा कारण महिला समानता को लेकर चल रहे आन्दोलन है। भारत की बेटियां आज अंतरिक्ष से लेकर खेल के मैदान तक में बुलंदियां छू रही हैं। वे परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में उल्लेखनीय भूमिकाओं का निर्वाह कर रही है। सरकार द्वारा ह्यबेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओह्र्, ह्रासुकन्या समृद्धि योजनाह्र् जैसे सराहनीय पहल के जरिए बेटियों को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। इक्कीसवीं सदी की चौखट पर खड़ी दुनिया में बड़े व्यापक बदलाव हो रहे हैं। इसानी रिश्तों की अहमियत को लेकर भी नई सोच पनप रही है। अब अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारत और चीन में, लिंग अनुपात सामान्य या यहां तक कि बेटी की पसंद के संकेत दिखाने लगा है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि इस बदलाव की असल वजह क्या है? दरअसल, माता-पिता में यह धारणा बलवती होती जा रही है कि बेटियां उनकी ढलती उम्र में धीरे-धीरे अधिक विश्वसनीय देखभाल करने वाली साबित हो सकती हैं। उन्हें परिवार से गहरे तक जुड़े रहने की अधिक संभावना के रूप में देखा जाने लगा है। आज बेटियों को बेटों के मुकाबले बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शनकर्तां, परिवार सार-संभालकर्तां, माता-पिता के प्रति जिम्मेदारी निर्वाहकर्ता के रूप में देखा जाने लगा है। तेजी से कामकाजी दुनिया का

‘चूल्हे से चाँद तक’: चूल्हे की आँच से चाँद की कविता तक की यात्रा

इस संग्रह की कविताएं परंपरा और प्रतिरोध के बीच की वह खाई भरती हैं, जो पितृसत्ता ने पीढ़ियों से गहरी की है। इन कविताओं में स्त्री केवल ह्राप्रेरणाह्र् नहीं है, बल्कि वह स्वयं कविता है – जिसमें भाव भी है, लय भी और आक्रोश भी।

स्त्री की आत्मा से निकली चीखः चूल्हे से चाँद तक की यात्रा-संग्रह की शीर्षक कविता ही इस संकलन की आत्मा है। यह उस अनाम, अनदेखी स्त्री की कहानी है, जो इतिहास में दर्ज नहीं, पर हर घर की नींव रही है। कविता की आरंभिक पक्तियाँ ही पाठक को चौंका देती हैं:

न रच सकी इतिहास में जितनी लड़ाइयाँ,
उतनी लड़ी है वह – खामोश, मगर पूरी ताकत से।
यह कविता बताती है कि स्त्री की हर दैनिक गतिविधि एक संघर्ष है – परात में गूंथा आटा, माँजे गए बर्तन, आँखों की राख – सब कुछ क्रांति के प्रतीक है। जब वह चूल्हे से चाँद तक पहुँचती है, तो यह केवल भौगोलिक नहीं, आत्मिक और वैचारिक उड़ान है। कविता कहती है:

कविता ने जब यह पहचाना,
तब लिखी गई स्त्री की पहली मुकम्मल कहानी।
देशभक्ति की चुप सिसकियाँ: घूँघट से गुँज तक
यह कविता एक शहीद की मौत को केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए छाया हुआ शून्य मानती है। यह रचना वीरगाथा नहीं, भावनाओं की गठरी है, जिसमें हर सदस्य का दर्द गुंजता है:

शहीद होती है बहन की राखी,
जो अब सिर्फ़ तस्वीरों में कलाई तलाशती है।
शहीद होती है माँ की ममता,
जो दीपावली पर दीप बन जलती है –



हिस्सा बनने के कारण वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने से अनेक पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिये अधिक संवेदनशील है। ऐसा माना जाने लगा है कि बेटियां बेटों के मुकाबले में ज्यादा संवेदनशील होती हैं और जीवन के अंतिम पड़ाव में मां-बाप को सुरक्षा कवच प्रदान कर सकती हैं। जिसके चलते लोग बेटों के मुकाबले बेटियों को अपनी प्राथमिकता बनाने को तरजीह देने लगे हैं।

पश्चिमी देशों में गौद लेने और आईवीएफ के डेटा दिखाते हैं कि बेटियों को चुनने की दिशा में स्पष्ट झुकाव है। दरअसल, पश्चिमी देशों के एकल परिवारों में बेटे अपनी गृहस्थी बसाकर मां-बाप को उनके भाग्य पर छोड़ जाते हैं। भारत में भी यही स्थितियां देखने को मिल रही है। जबकि सदियों से भारत की समाज-व्यवस्था एवं परिवार-परम्परा पुत्र मोह की ग्रंथि से ग्रस्त रहा है। जिसके चलते शिशु लिंग अनुपात में असंतुलन बढ़ता गया है। देश में हुई 2016 की जनगणना में लड़कों की तुलना में लड़कियों की घटती संख्या के आंकड़े चौंकाते ही नहीं बल्कि दुखी भी करते हैं। जिस तरह से लड़के-लड़कियों का अनुपात असंतुलित हो रहा है, उससे ऐसी चिन्ता भी जतायी जाने लगी है कि यही स्थिति बनी रही तो लड़कियां कहां से लाएंगे? हालात यह है कि आंध्र प्रदेश में 2016 में प्रति एक हजार लड़कों के मुकाबले महज आठ सौ छह लड़कियों का जन्म दर्ज किया गया। हालांकि, अब आधिकारिक आंकड़े बता रहे हैं कि देश में शिशु लिंग अनुपात दर में सुधार हुआ है।

जन्म से पहले ही पता चल जाए कि लड़की यानी बालिका पैदा होगी तो माता-पिता उसकी जान लेने से भी नहीं कतराते। कन्या भ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाएं इसी सोच का परिणाम बनी। पिछली सदी में समाज के एक बड़े वर्ग में यह एक विभीषिका ही थी कि परिवार की धुरी होते हुए भी नारी को वह स्थान प्राप्त नहीं था जिसकी वह अधिकारिणी थी। उसका मुख्य कारण था सदियों से चली आ रही कुरीतियाँ, अंधविश्वास व बालिका शिक्षा के प्रति



बिना उत्तर के। यहाँ प्रियंका ने सैनिक के परिवार के टूटते तंतुओं को ऐसा काव्यात्मक आकार दिया है, जो किसी रिपोर्ताज से अधिक विश्वसनीय और मार्मिक लगता है।

प्रेम की पुनर्परिभाषा
वो स्त्रियाँ सौभाग्यशाली थीं
यह कविता समकालीन स्त्री विमर्श में प्रेम की एक नई भाषा गढ़ती है। यह स्त्री को पूजा की वस्तु नहीं बनाती, बल्कि उसे बराबरी का स्पर्श देती है। प्रियंका सौरभ लिखती हैं:

वो पुरुष जो प्रेम में पूजा नहीं,
पर बराबरी का स्पर्श दे सका।
जो स्त्री को ‘कम’ नहीं,
‘कभी’ नहीं कह सका।
इस कविता की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह ह्राप्रेमह्र् को बिना रूलेमर के, पूरी आत्मीयता से प्रस्तुत करती है – जहाँ स्त्री एक व्यक्ति बनती है, न कि केवल रिश्तों में गूँथी गई एक परछाई।

आत्मसंथन का महाभारत
‘तुम शकुनि नहीं, पर बनते क्यों हो?’

यह रचना एक आत्मालोचनात्मक प्रस्तुति है, जो पाठक से संवाद करती है। कविता किसी दूसरे को नहीं, बल्कि स्वयं को संबोधित है – अपने भीतर के षड्यंत्र को पहचानने की कोशिश:

तुम्हारे भीतर की महाभारत,
अभी भी अधूरी है, जारी है।
जागो उस भीतर के युद्ध से,
और अपने साये को स्वीकारो।
यह कविता बहुत कम शब्दों में वह बेचैनी पैदा करती है, जो समाज को नहीं, व्यक्ति को बदलने का आग्रह करती है।

शिक्षा और पक्षपात की त्रासदी
द्रोणाचार्य की वर्ग नीति
प्रियंका की यह कविता हमारे सामाजिक-शैक्षणिक ढाँचे की पोल खोलती है। ‘द्रोणाचार्य’ जैसे प्रतिष्ठित प्रतीक के माध्यम से वह यह दिखाने में सफल होती हैं कि न्याय केवल शिक्षा नहीं, साहस भी मांगता है:

ज्ञान बंटना मेरा कर्म था,
पर न्याय कहीं खो गया।
वर्ग नीति ने उसे बंदी बना लिया।

संकीर्णता। कितनी विडम्बना है कि देश में हम ह्राबेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओह्र् का नारा बुलन्द करते हुए एक जोरदार मुहिम चला रहे हैं उस देश में लगातार बालिकाओं की संख्या घटने का दाग लगता रहा है। यह दाग ह्राएक भारत, श्रेष्ठ भारतह्र् के संकल्प पर भी लगा है और यह दाग हमारे द्वारा नारी को पूजने की परम्परा पर भी लगा है। लेकिन प्रश्न है कि हम कब बेदाग होंगे? लेकिन अब इस संकीर्ण सोच में बदलाव आना एक सुखद संकेत है।

अच्छे भविष्य के लिए हम बेटियों की पढ़ाई से ही सबसे ज्यादा उम्मीदें बांधते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे नारे हमारे संकल्प को बताते हैं, हमारी सदिच्छा को दिखाते हैं, भविष्य को लेकर हमारी सोच को जाहिर करते हैं, लेकिन वर्तमान की हकीकत इससे उलट है, इसे बदलने में अभी भी लम्बा सफर तय करना होगा। बालिकाएं पढ़ाई में अपने झंडे भले ही गाड़ दें, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की क़ूताएं कई तरह की हैं। शताब्दियों से हम साल में दो बार नवरात्र महोत्सव मनाते हुए कन्याओं को पूजते हैं। लेकिन विडम्बना देखिये कि सदियों की पूजा के बाद भी हमने कन्याओं को उनका उचित स्थान और सम्मान नहीं दे पाये हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) का सर्वे चिंता बढ़ाने वाला है। सर्वे के अनुसार, लगभग 15 फीसदी भारतीय माता-पिता अभी भी बेटियों की तुलना में बेटों की आकांक्षा रखते हैं। यही वजह है कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में विषम शिशु लिंगानुपात चिंता का विषय बना हुआ है। लड़कियों को भावनात्मक लगाव या घरेलू स्थिरता के लिये तो महत्व दिया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि पोषण, शिक्षा या विरासत तक उन्हें समान पहुंच दी जाए। भारतीय समाज में दहेज जैसी सांस्कृतिक प्रथाएं आज भी बेटी के माता-पिता की बड़ी चिंता बनी रहती हैं। परंपरावादी समाज में यह धारणा बलवती रही है कि बेटियां दूसरे परिवार की हैं। यही वजह है कि ग्रामीण और शहरी गरीब समुदायों में लड़कियां हाशिये पर रख जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत को लिंग समानता के वैश्विक आंदोलन की किसी भी तरह अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 वैश्विक लैंगिक अंतर का आकलन और तुलना करने के लिए एक समझने योग्य ढांचा प्रदान करके और उन देशों को उजागर करके जो इन संसाधनों को महिलाओं और पुरुषों के बीच समान रूप से विभाजित करने में रोल मॉडल हैं, रिपोर्ट अधिक जागरूकता के साथ-साथ नीति निमाताओं के बीच अधिक आदान-प्रदान के लिए उत्प्रेरक का काम करती है। भारत में समान संपत्ति अधिकार लागू करने, दहेज प्रथा की कुरीति को समाप्त करने की दिशा में सख्त कदम उठाने चाहिए। तभी भारतीय समाज में लिंगभेद की मानसिकता खत्म होगी और लैंगिक समानता की दिशा में मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही देश में तेजी से बढ़ती बुजुर्गों की आबादी के लिये बालिकाएं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में आधार बन सकेगी।

पंचायत वेबसरीज के बम बहादुर हैं रंगाश्रम गोरखपुर की उपज
इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पंचायत वेब सीरीज धूम मचाई हुई है। पंचायत वेबसीरीज के लगभग सभी किरदार एक से बढ़कर एक हैं। इस वेब सीरीज के सभी कलाकारों ने दिल से मेहनत किया है,,साथ ही साथ डाइरेक्टर साहब का निर्देशन भी लाजवाब है। पंचायत की कहानी हमारे समाज के ग्रामीण परिवेश को बारीकी से दर्शा रही है,,,इस वेब सीरीज की लेखन भी लाजवाब है। वैसे तो इस वेबसीरीज मे सभी कलाकारों के अभिनय शानदार है। इस वेब सीरीज में कैरेक्टर बमहादुर जो हॉ (बम बहादुर) जिसकी भूमिका (अमित कुमार मौर्य) ने निभाई है। अमित जो जी मूलरूप से महाराजगंज जिले से ताल्लुक रखते हैं। अमित कुमार मौर्य को मैं निजी तौर पर जानता हूँ। वे जितने अच्छे कलाकार हैं कही उससे अधिक वो निजी जीवन एके अच्छे इंसान भी हैं। अमित बेहद सादगी परक व्यक्ति हैं। चेहरे पर उनके हरपल मुस्कान सजी रहती हैं। मैंने एक लम्बी अवधी तक अमित के साथ काम किया है। और एक लंबा समय भी बिता चुका हूँ। इसलिए मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। अमित कितने सुलझे हुए इंसान हैं। अमित को संघर्ष करते हुए और सफल होते हुए दोनों अवस्था को,मैं अपनी आँखों से देखा हूँ। अमित पंचायत वेब सीरीज के तीसरे भाग मे तेज दौड़ने की वजह से सुखियों मे बने रहे वहीं, वर्तमान मे पंचायत वेब सीरीज मे चौथे भाग मे वो कैच करने की वजह से लोगों के बीच छाप हुए हैं। अमित कुमार मौर्य ने अभिनय की शुरुआत तो स्कूल टाइम से ही कर दिये थे। लेकिन थियेटर को जॉइन उन्होंने गोरखपुर आकर किये थे। अमित उन दिनों अपना सोखने और गोरखपुर मे रहने खाने का खर्च निकालने के लिए ऑर्किटेक्ट.फ़ोल्ड मे जॉब भी किया करते थे। अमित कुमार मौर्य गोरखपुर मे अभिनय की शिक्षा (रंगाश्रम) से लिए हैं,, जिसमे उन दिनों मैं भी उनके साथ था । मैं और अमित दोनों एक ही बैच के स्टूडेंट्स हैं। परिवार के सपोर्ट न मिलने के कारण मैंने अपना खुद का अभिनय सफर आधे सफर मे ही छोड़ दिया था। मगर अमित इस मामले मे मेकी थे ,उनके परिवार के लोगों ने सपोर्ट किया और अमित ने भी मेहनत मे कोई कसर नहीं छोड़ी आखिरकार एक दिन अमित को मेहनत रंग लाई। और अमित को मिली एक नई पहचान पंचायत वेब सीरीज के बमहादुरके रोल से।अमित ने अभिनय की शुरुआत रंगाश्रम गोरखपुर से किये हैं इसलिए यह कहना उचित होगा की पंचायत वेबसीरीज के बम बहादुर हैं रंगाश्रम ,गोरखपुर की उपज।

नौरज कुमार सिंह
देवरिया, उत्तर प्रदेश

टिकाऊ भूमि प्रबंधन और कृषि के लिए गंभीर चुनौती बनता जलवायु परिवर्तन



विश्व का 95 प्रतिशत भोजन कृषि भूमि पर उत्पादित होता है, यही भूमि हमारी खाद्य प्रणालियों का आधार है लेकिन चिंता का विषय है कि इसमें से एक तिहाई भूमि वर्तमान में क्षरित हो चुकी है, जो दुनियाभर में 3.2 बिलियन लोगों को प्रभावित करती है, विशेष रूप से ग्रामीण समुदायों और छोटे किसानों को, जो अपनी आजीविका के लिए भूमि पर निर्भर हैं, जिससे भूख, गरीबी, बेरोजगारी और जबरन पलायन में वृद्धि होती है। जलवायु परिवर्तन इन मुद्दों को और गंभीर बना देता है, जिससे टिकाऊ भूमि प्रबंधन और कृषि के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न होती हैं तथा पारिस्थितिकी तंत्र का लचीलापन कमजोर हो जाता है। जलवायु संकट जख्मा, बाढ़, जंगलों में आग लगने की घटनाओं के जरिये मरुस्थलीकरण को बढ़ा रहा है। एक और जहां जलवायु का गहराता संकट मरुस्थलीकरण की समस्या को बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर मरुस्थलीकरण जलवायु संकट को और गंभीर बना रहा है अर्थात् मरुस्थलीकरण और जलवायु संकट एक-दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। जलवायु संकट में भू- क्षरण की भी बहुत बड़ा योगदान है। पर्यावरणविदों के मुताबिक मिट्टी में वातावरण में मौजूद कार्बन से तीन गुना ज्यादा कार्बन है और पृथ्वी पर मौजूद कार्बन का सबसे बड़ा भंडार मिट्टी में ही है। कार्बन का

उत्सर्जन मिट्टी से निकलकर वातावरण में पहुंचकर वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी कर रहा है और मरुस्थलीकरण के कारण यह समस्या और ज्यादा बढ़ रही है। पृथ्वी का निरन्तर बढ़ता तापमान, सौर ऊर्जा और हवा की प्रकृति में भी बदलाव ला रहा है। आंकड़ों के अनुसार विश्वभर में कुल कार्बन उत्सर्जन के 10–12 फीसदी (3.6–4.4 बिलियन टन) उत्सर्जन के लिए भू-क्षरण जिम्मेदार है और भारत को तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक माना जाता है, जहां कुल उत्सर्जित कार्बन डाईऑक्साइड की तुलना में भू-क्षरण से 50 फीसदी ज्यादा कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है। सूखा मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को तेज कर देता है और भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा भाग तो शुष्क इलाकों में ही रहता है। देश का लगभग 70 प्रतिशत भूभाग (करीब 22.83 करोड़ हेक्टेयर) शुष्क माना गया है और इस शुष्क भूभाग की उत्पादकता काफी कम है। देश का करीब 7.36 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्रफल मरुस्थलीकरण से प्रभावित है और भारत के कई इलाके तो प्रायः सूखे की चपेट में रहते हैं। विश्व में मौजूद कुल मवेशियों का 8 फीसदी पालन भारत में होता है जबकि भारत में दुनियाभर में मौजूद

कुल चरागाहों का केवल आधा फीसदी ही भारत में है। इसी प्रकार भारत के पास विश्व के कुल स्थल भाग का केवल 2.4 फीसदी ही है लेकिन कुल मानव आबादी का 18 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा हमारे देश में ही है।

विश्व के अन्य शुष्क इलाकों की तुलना में भारत के शुष्क इलाकों में मानव आबादी और मवेशियों का दबाव कहीं ज्यादा है। मनुष्यों और मवेशियों का यह असहनीय दबाव मरुस्थलीकरण की समस्या को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। शुष्क इलाकों का प्राकृतिक तंत्र मनुष्यों द्वारा डाले जाने वाले अनावश्यक दबाव के कारण चरमराने लगता है और इस विघटनकारी प्रक्रिया को नहीं रोके जाने की स्थिति में समूचा तंत्र रेगिस्तान की भेंट चढ़ जाता है। लकड़ी के लिए पेड़ों की अंधाधुंध छंटाई अथवा अत्यधिक चराई के कारण उस तंत्र में प्राकृतिक उपयोगी पौधों की संख्या काफी घट जाती है, जि स्थान अनुपयोगी और अखाद्य पेड़-पौधे ले लेते हैं, जिसका दुष्परिणाम यही होता है कि वह प्राकृतिक तंत्र पहले से भी बहुत कम संख्या में मनुष्यों और मवेशियों को पोषित कर पाता है. और यही दुष्चक्र मरुस्थलीकरण को गति प्रदान करता है। रेगिस्तानी इलाकों में चूँकि बारिश बहुत ही अनियमित ढंग से होती है, ऐसे में ऐसे इलाकों

में उपलब्ध पानी की बेहद सीमित मात्रा से कृषि उत्पादकता पर काफी असर पड़ता है। वैसे तो शुष्क इलाकों में वर्षा कम होती है लेकिन जो वर्षा होती है, वह काफी तेज और तुफानी किस्म की होती है, जिससे प्रायः ऐसे इलाकों में बारिश बाढ़ का रूप लेकर उपजाऊ मिट्टी को ही बहा ले जाती है और वहां बड़े-बड़े गड्ढे तथा नाले बन जाते हैं, जो प्रायः खेती के लिए बेकार हो जाते हैं।

कई क्षेत्रों में इसी के चलते रेत के बड़े-बड़े टीले बन जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष बंजर इलाकों में प्रति हेक्टेयर क्षेत्र से पानी के कटाव के कारण 16.35 टन मिट्टी बह जाती है।

बार-बार आने वाला सूखा मरुस्थलीकरण की प्र-क्रिया को तेज कर देता है। मिट्टी का कटाव होने का एक दुष्परिणाम यह भी है कि पानी के साथ वहकर आने वाली मिट्टी जलाशयों में भर जाती है, जिससे उनकी जलधारण क्षमता घट रही है और इस कारण बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। बीते कुछ वर्षों से देश के कई इलाकों में लाखों लोगों को बारिश के कारण बाढ़ का कहर झेलने को विवश होना पड़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। यही नहीं, बड़ी-बड़ी पनबिजली परियोजनाओं के सरोवरों में मिट्टी भर जाने से उनसे निर्मित होने वाली बिजली की

मात्रा भी घट जाती है। जहां तक वातावरण में कार्बन कम करने का सवाल है तो तापमान में डेढ़ डिग्री सेल्सियस कमी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वातावरण से कार्बन को तेजी से सोखने की जरूरत है और पर्यावरणविदों के मुताबिक यह प्राकृतिक कार्बन सिंक की क्षमता में वृद्धि करके ही हो सकता है और जंगलों तथा कृषि की समस्या को कम करने वाले सिंक मैकेनिज्म से एक तिहाई से भी ज्यादा जलवायु आपदा कम की जा सकती है। इसका सबसे बेहतर तरीका यही माना जा रहा है कि कार्बन को वनों, चारागाह और मिट्टी में समेट दिया जाए, जो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए भी बेहद जरूरी है।

वनीकरण, वनस्पति कवर में सुधार, जल का दक्षतापूर्ण उपयोग, मिट्टी के कटाव को बेहतर कृषि पद्धति के जरिये कम करना इत्यादि उपायों के जरिये मिट्टी में बायोमास उत्पादन और जैविक कार्बन कंटेेंट में सुधार संभव है। पर्यावरणविदों का मानना है कि जंगलों का नुकसान रोककर और दोबारा लगाकर 2050 तक 150 बिलियन टन से भी ज्यादा कार्बन कम किया जा सकता है और इस अवधि में शुष्क क्षेत्रों में कृषि भूमि के अलावा 30–60 बिलियन टन कार्बन का संचय किया जा सकता है।

एक नई तरह की डरावनी कहानी माँ

एक नई तरह की डरावनी कहानी,माँ एक ऐसी फिल्म है जो भारतीय हॉरर फिल्मों के पुराने ढांचे से बाहर निकलती है। डायरेक्टर विशाल फुरिया ने इसमें वो डर दिखाया है जो सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस होता है। यहां ना तेज म्यूजिक है, ना अचानक उभरते भूत, बल्कि एक ऐसी मां की कहानी है जो अपनी बेटी के लिए राक्षसी ताकतों से भिड़ जाती है।

कहानी की शुरूआत होती है चंद्रपुर नाम के एक रहस्यमय गांव से, जो हर वक्त कोहरे में डूबा रहता है। वहां की खामोशी में एक मां अंबिका का दुख छिपा है, जिसकी बेटी पर एक भयानक श्राप का साया है। ये श्राप ही उस मां को देवी जैसी ताकत दिलाता है।

अंबिका का किरदार एक आम महिला से शुरू होकर एक अद्भुत शक्ति में बदलता है। जब उसकी आंखों में डर की जगह हिम्मत और गुस्सा उतरता है, तब दर्शक समझते हैं कि अब कहानी ने रुख बदल लिया है। यह सिर्फ एक बेटी को बचाने की लड़ाई नहीं, बल्कि बुराई के खिलाफ युद्ध है।

काजोल ने अंबिका के रोल में ऐसा काम किया है जो लंबे समय तक याद रहेगा। उनके चेहरे के हावभाव, चुप्पी और ताकतवर डायलॉग्स, सब कुछ असरदार है। श्वेता के रोल में खेरीन शर्मा भी काफी सच्ची लगती हैं। रोनित रॉय की मौजूदगी कहानी में एक अजीब सा रहस्य भर देती है, जो कहानी को और मजबूत करता है। वहीं, इंद्रनील सेनगुप्ता, जितिन



गुलाटी, गोपाल सिंह, यानिया भारद्वाज और रूपकथा चक्रवर्ती ने भी अपना सौ प्रतिशत दिया है।

विशाल फुरिया ने डर को आवाजों और भूतों से नहीं, माहौल से रचा है। फिल्म के जंगल, मंदिर और वीरान गलियों में जो सन्नाटा है, वही असली डर पैदा करता है। यह हॉरर का एक शांत लेकिन असरदार रूप है। कहा जाए तो विशाल फुरिया ने खुबसूरती से

कहानी को आकर दिया है।

फिल्म में पौराणिक कहानी हारक्तबीजल्लू और देवी काली को आज के सिस्टम से जोड़ा गया है। यह दिखाया गया है कि असली राक्षस अब भी हमारे समाज में हैं और वह भी डर, चुप्पी और गलत सोच के रूप में। इस तरह से फिल्म चुपचाप एक गहरी बात कह जाती है। फिल्म में ह्यकाली शक्तिह्म गाना और कई सीन इतने ताकतवर हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शत्रु कैमरा वर्क और साउंड डिजाइन इतने अच्छे हैं कि चंद्रपुर की गलियां और मंदिर बिल्कुल असली लगते हैं। क्या कोई मां सच में देवी बन सकती है? एक श्राप पीढ़ियों तक कैसे असर करता है? बुराई से लड़ाई में अकेली मां कितना आगे जा सकती है? क्या परंपरा और आधुनिक सोच साथ आ सकती हैं? अगर ये सवाल आपके मन में उठते हैं, तो ह्यमाँल्लू फिल्म का जवाब जरूर दीजिए। माँ सिर्फ डर की कहानी नहीं है, यह ममता, आस्था और हिम्मत की कहानी है। इसमें जिस तरह से इमोशन और हॉरर को मिलाया गया है, उस चीज ने इसे एक मस्त वॉच वॉच फिल्म बना दी है। तो इस वीकेंड देखिए यह फिल्म जो आपके लिए बन जाएगी एक बेहतरीन अनुभव।

डायरेक्टर: विशाल फुरिया कास्ट: काजोल, रोनित रॉय, इंद्रनील सेनगुप्ता, खेरीन शर्मा, जितिन गुलाटी, गोपाल सिंह, सुर्यशिखा दास, यानिया भारद्वाज, रूपकथा चक्रवर्ती।

जुगनू: स्मृति, जैविक चेतना व उम्मीद का प्रतीक

जुगनू के बहाने बदलाव दस्तक दे रहा है जिसमें पर्यावरण संरक्षण, रोजगार और जैव विविधता एक साथ पनप रहे हैं। भंडारदरा, राजमाची प्रबल माची और कर्जत जैसे क्षेत्र जुगनू उत्सव के लिए जाने जा रहे हैं।

आदिवासी समाज ने जुगनुओं की घटती संख्या को एक चेतावनी के रूप में देखा और प्राक्रतिक को समय रहते बचाने की ओर एक पहल की। जुगनुओं की मौजूदगी बताती है कि मिट्टी, पानी और हवा अब भी जीवंत है लेकिन पिछले कुछेक दशकों में बिजली के प्रसार, कीटनाशकों के उपयोग और शहरी संस्कृति के प्रभाव से जुगनुओं का परिवेश सिकुड़ने लगा। इस संकट को अवसर में बदलने का काम ग्रामीणों ने किया। उन्होंने जुगनुओं की प्राकृतिक जीवन शैली को समझा और उनके प्रजननकाल यानी मानसून पूर्व महीनों में कृत्रिम रोशनी से दूरी बनानी शुरू की। गांवों में रात के समय लाइट



बंद करके रखने की परंपरा शुरू की गई है ताकि जुगनू अंधेरे में अपने जीवन चक्र को पूरा कर सके। इसका नतीजा यह हुआ कि इन गांवों में हर साल हजारों पर्यटक जुगनू फेस्टिवल देखने आते हैं और ग्रामीणों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलते हैं। अब इन गांवों में होम स्टे चल

रहे हैं। स्थानीय गाइड पर्यटकों को जंगल में ले जाते हैं। महिलाएं हस्तशिल्प बेचती हैं और युवा जुगनुओं की लोक कथाएं सुनाते हैं। यह सब पर्यटन नहीं एक स-ंस्कृतिक पुनरुत्थान है जिसमें गांव अपनी जड़ों से फिर जुड़ रहा है। विश्व स्तर पर भी ऐसी कोशिशें हो रही हैं कि मैक्सिको के नाना कामिल्पा क्षेत्र में प्रतिवर्ष फायर फ्लाई सीजन देखने

को हजारों लोग पहुंचते हैं। जुगनुओं के बहाने हमे यह समझने का मौका मिलता है कि कोई भी कीट कमतर नहीं होता, अगर उसे समझने का नजरिया बदल दिया जाए। महाराष्ट्र के आदिवासी गांव और नाना कामिल्पा की पहाडियां यह सिखा रही है कि प्र-कृति को बचाने की शुरूआत कहाँ से हो सकती है। जहां हम कभी बच्चों की तरह चमत्कार खोजा करते थे। जुगनु अब सिर्फ कीट नहीं रहे, वे उस सामुहिक स्मृति, जैविक चेतना व उम्मीद का प्रतीक बन गए हैं जो अंधेरे में भी टिमटिमा सकते हैं। बशर्ते हम उसे देखना चाहें।

जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाएं

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 50 आधार बिंदुओं की कमी की है। इसके साथ ही, निजी क्षेत्र के बैंकों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं क्रेडिट कार्ड कम्पनियों सहित अन्य वित्तीय संस्थानों ने भी अपने ग्राहकों को प्रदान की जा रही ऋणराशि पर लागू ब्याज दरों में कमी की घोषणा करना प्रारम्भ कर दिया है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में की गई कमी का लाभ शीघ्र ही भारत में ऋणदाताओं तक पहुंच सके एवं इससे अंततः देश की अर्थव्यवस्था को बल मिल सके। भारत में चूँकि अब मुद्रा स्फीति की दर नियंत्रण में आ गई है, अतः आगे आने वाले समय में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में और अधिक कमी की जा सकती है। इस प्रकार, बहुत सम्भव है ऋणराशि पर लागू ब्याज दरों में कमी के बाद कई नागरिक जिन्होंने पूर्व में कभी बैंकों से ऋण नहीं लिया है, वे भी ऋण लेने का प्रयास करें। बैंक से ऋण लेने से पूर्व इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि इस ऋण को चुकता करने की क्षमता भी ऋणदाता में होनी चाहिए अर्थात ऋणदाता की पर्याप्त मासिक आय होनी चाहिए ताकि बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण की किश्त एवं ब्याज का भुगतान पूर्व निर्धारित समय सीमा के अंदर किया जा सके। इस संदर्भ में विशेष रूप से युवा ऋणदाताओं द्वारा क्रेडिट कार्ड के उपयोग पश्चात संबंधित राशि का भुगतान समय सीमा के अंदर अवश्य करना चाहिए क्योंकि अन्यथा क्रेडिट कार्ड एजेंसी द्वारा चूक की गई राशि पर भारी मात्रा में ब्याज वसूला जाता है, जिससे युवा ऋणदाता ऋण के जाल में फंस जाते हैं।

बैंकों से लिए गए ऋण की मासिक किश्त एवं इस ऋणराशि पर ब्याज का भुगतान यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं किया जाता है तो चूककर्ता ऋणदाता से बैंकों द्वारा दंडात्मक ब्याज की वसूली की जाती है। इसी प्रकार, कई नागरिक जो क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं एवं इस क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध उपयोग की गई राशि का भुगतान यदि वे निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं कर पाते हैं तो इस राशि पर चूक किए गए क्रेडिट कार्ड धारकों से भारी भरकम ब्याज की दर से दंड वसूला जाता है। कभी कभी तो दंड की यह दर 18 प्रतिशत से 24 प्रतिशत के बीच रहती है। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले नागरिक कई बार इस उच्च ब्याज दर पर वसूली जाने वाली दंड की राशि से अनभिज्ञ रहते हैं। अतः बैंकों से लेी जाने वाली ऋणराशि एवं क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली राशि का समय पर भुगतान करने के प्रति ऋणदाताओं को सजग रहने की आवश्यकता है।

कुल मिलाकर यह ऋणदाताओं के हित में है कि वे बैंक से लिए जाने वाले ऋण की राशि तथा ब्याज की राशि एवं क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली राशि का पूर्व निर्धारित एवं उचित समय सीमा के अंदर भुगतान करें क्योंकि अन्यथा की स्थिति में उस चूककर्ता नागरिक की क्रेडिट रेटिंग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है एवं आगे आने वाले समय में उसे किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है एवं बहुत सम्भव है कि भविष्य में उसे किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त ही न हो सके।

ऋणदाता यदि किसी प्रामाणिक कारणवश अपनी किश्त एवं ब्याज का बैंकों अथवा क्रेडिट कार्ड कम्पनी को समय पर भुगतान नहीं कर पाता है और उसका

ऋण खाता यदि गैर निष्पादनकारी आस्ति में परिवर्तित हो जाता है तो इस संदर्भ में चूककर्ता ऋणदाता द्वारा बैंकों को समझौता प्रस्ताव दिए जाने का प्रावधान भी है। इस समझौता प्रस्ताव के माध्यम से चूककर्ता ऋणदाता द्वारा सम्बंधित बैंक अथवा क्रेडिट कार्ड कम्पनी को मासिक किश्त एवं ब्याज की राशि को पुर्ननिर्धारित किए जाने के सम्बंध में निवेदन किया जा सकता है। परंतु, यदि ऋणदाता ऋण की पूरी राशि, ब्याज सहित, अदा करने में सक्षम नहीं है तो चूक की गई राशि में से कुछ राशि की छूट प्राप्त करने एवं शेष राशि को एकमुश्त अथवा किश्तों में अदा करने के सम्बंध में भी समझौता प्रस्ताव दे सकता है। ऋण की राशि अथवा ब्याज की राशि के सम्बंध के प्राप्त की गई छूट की राशि का रिकार्ड बनता है एवं समझौता प्रस्ताव के अंतर्गत प्राप्त छूट के चलते भविष्य में उस ऋणदाता को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान चूककर्ता ऋणदाता को रखना चाहिए। अतः जहां तक सम्भव को ऋणदाता द्वारा समझौता प्रस्ताव से भी बचा जाना चाहिए एवं अपनी ऋण की निर्धारित किश्तों एवं ब्याज का निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत भुगतान करना ही सबसे अच्छा रास्ता अथवा विकल्प है।

भारत में तेज गति से हो रही आर्थिक प्रगति के चलते मध्यमवर्गीय नागरिकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, जिनके द्वारा चार पहिया वाहनों, स्कूटर, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन एवं मकान आदि आस्तियों को खरीदने हेतु बैंकों अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया जा रहा है। कई बार मध्यमवर्गीय परिवार एक दूसरे की देखा देखी आपस में होड़ करते हुए भी कई उत्पादों को खरीदने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं, चाहे उस उत्पाद विशेष की आवश्यकता हो अथवा नहीं। उदाहरण के लिए एक पड़ोसी ने यदि अपने चार पहिया वाहन का एकदम नया मॉडल खरीदा है तो जिस पड़ोसी के पास पूर्व में ही चार पहिया वाहन उपलब्ध है वह पुराने मॉडल के वाहन को बेचकर पड़ौसी द्वारा खरीदे गए नए मॉडल के चार पहिया वाहन को खरीदने का प्रयास करता है और बैंक के ऋण के जाल में फंस जाता है। यह नव धनाढ्य वर्ग यदि बैंक से लिए गए ऋण की किश्त एवं ब्याज की राशि का निर्धारित समय सीमा के अंदर भुगतान नहीं कर पाता है तो उस नागरिक विशेष के वित्तीय रिकार्ड पर धब्बा लग सकता है जिससे उसके लिए उसके शेष जीवन में बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से पुनः ऋण लेने में कठिनाई आ सकती है। अतः बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले नागरिकों को ऋण की किश्त का समय पर भुगतान करना स्वयं उनके हित में है, ताकि भारत में तेज हो रही आर्थिक प्रगति का लाभ आगे आने वाले समय में भी समस्त नागरिक ले सकें।

भारत में तो यह कहा भी जाता है कि जिसके पास जितनी चादर हो, उतने ही पैर पसारने चाहिए। अर्थात, नागरिकों को बैंकों से ऋण लेते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऋण की किश्त एवं ब्याज की राशि का भुगतान करने लायक उनकी अतिरिक्त आय होनी चाहिए, ताकि ऋण की किश्तों एवं ब्याज की राशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के अंदर किया जा सके एवं उनका ऋण खाता गैर निष्पादनकारी आस्ति में परिवर्तित नहीं हो।



हिन्दी को संघर्ष का नहीं, सेतु का माध्यम बनाएं

दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में हिन्दी विरोध की राजनीति अब महाराष्ट्र में भी उग्र से उग्रतर हो गयी, इसी के कारण त्रिभाषा नीति को महाराष्ट्र में लगा झटका दुखद और अफसोसजनक है। आखिरकार राजनीतिक दबाव, लंबी रस्साकशी और कशमकश के बाद महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई से जुड़े मुद्दे पर यू-टर्न लेते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए। विदित हो कि केंद्र सरकार की नीति के तहत महाराष्ट्र के स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाना था। राजनीतिक आग्रहों एवं दुराग्रहों के चलते अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मतलब, महाराष्ट्र को तीसरी भाषा के रूप में भी हिंदी मंजूर नहीं है। महाराष्ट्र में हिंदी का संकट वास्तव में एक गहरे सामाजिक-राजनीतिक विमर्श का हिस्सा है। यह केवल भाषाई नहीं, बल्कि अस्मिता, पहचान और सह-अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। जबकि भाषा को संघर्ष का नहीं, सेतु का माध्यम बनाना चाहिए। क्योंकि जब मराठी और हिंदी एक-दूसरे की सहयोगी बनेंगी, तभी महाराष्ट्र और भारत दोनों का भविष्य उज्ज्वल होगा और तभी महाराष्ट्र राष्ट्रीयता से जुड़े हुए समग्र विकास की ओर अग्रसर हो सकेगा। हिन्दी को हथियार बनाकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मराठी समर्थक राजनीति को इस तरह से गरमा दिया था कि सरकारी प्रयासों के हाथ-पांव फूलने लगे और अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ा। ठाकरे बंधुओं का हिन्दी विरोधी आंदोलन दिनोंदिन उग्र होता जा रहा था। यह सच है, हर राज्य के लिए भाषा की राजनीति मायने रखती है और कोई भी पार्टी स्थानीय स्तर पर अपनी क्षेत्रीय भाषा से मुंह नहीं मोड़ सकती। यह सर्वविदित है कि महाराष्ट्र में पूर्व में एक समिति ने जब हिंदी पढ़ाने की सिफारिश की थी, तब उद्धव ठाकरे ही राज्य के मुख्यमंत्री थे। तब हिंदी का मामला बढ़ा नहीं था, पर आज जब ठाकरे विपक्ष में हैं, तब यही मुद्दा सबसे अहम हो गया है। शायद यह शर्म की बात है कि जिस राज्य की राजधानी में पूरा हिंदी फिल्म उद्योग बसता है, समूचे देश की आर्थिक राजधानी होने का गौरव जिसे मिला हुआ है, जहां समूचे देश के लोगों बसे है, जिसे सांझा-संस्कृति का गौरव प्राप्त है, उस राज्य की राजनीति अब हिंदी से परहेज करती दिख रही है। आज उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस सरकार मराठी मानुष की शक्ति से हार गई, पर वे इस बात को छिपा रहे हैं कि हारी सरकार नहीं, बल्कि राष्ट्र-भाषा हिंदी हारी है, जिसने मुंबई को सपनों का शहर बनाए रखा है। भारत विविधताओं का देश है, यहां भाषाएं न केवल संवाद का माध्यम हैं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी हैं। परंतु जब भाषाएं टकराव का विषय बन जाएं, तो वह केवल भाषाई संकट नहीं रह जाता, बल्कि एक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दा बन जाता है। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जहां हिंदी भाषा को लेकर एक अनकहा-अनचाहा-सा संघर्ष चल रहा है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा केवल एक भाषा नहीं, बल्कि मराठी अस्मिता का प्रतीक है। कई मराठी संगठनों और राजनीतिक दलों का यह मानना है कि हिंदी भाषा का बढ़ता वर्चस्व मराठी संस्कृति के लिए खतरा बन सकता है। फडणवीस सरकार की ताजा घोषणा यह दर्शा रही है कि हिंदी का मुद्दा राज्य में विपक्षी दलों के हाथों का एक ताकतवर राजनीतिक हथियार बनता जा रहा था। न केवल विपक्ष के सभी दल इस मसले पर एकजुट और विधानसभा के मॉनसून सत्र को हंगामेदार बनाने पर आमादा थे, बल्कि ठाकरे बंधुओं को भी हिंदी विरोध की राजनीति की अपनी जानी-पहचानी जमीन वापस मिलती दिख रही थी। क्योंकि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के शुरूआती दौर में पार्टी खास तौर पर हिंदीभाषियों के विरोध के लिए जानी जाती थी। मुंबई और महाराष्ट्र में हिंदीभाषियों की निरंतर बढ़ती आबादी को शिवसेना मराठी अस्मिता के लिए खतरे के रूप में देखती थी। हालांकि बाद के दौर में, खासकर नब्बे के दशक से भाजपा के गठबंधन में शिवसेना की राजनीति भी हिंदी से हिंदू की ओर मुड़ती गई। ऐसे में निश्चित ही मराठा राजनीति से हिन्दी विरोध की उम्मीद नहीं थी। अब तक तमिलनाडु को ही हिंदी विरोध के लिए जाना जाता था, पर इधर तीखे हिंदी विरोध में कर्नाटक के साथ ही, महाराष्ट्र भी शामिल हो गया है। दुनिया की सर्वाधिक तीसरी बोली जाने वाली हिन्दी भाषा अपने ही देश में उपेक्षा एवं राजनीति की शिकार है। अब केन्द्र सरकार के साथ-साथ हिंदी समाज को ज्यादा सजग होना पड़ेगा। हिन्दी भाषी प्रांतों को अपनी राजनीतिक व आर्थिक शक्ति को इतना बल देना पड़ेगा कि कम से कम तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अहिंदीभाषी राज्यों में स्वीकार किया जाए।

हिंदी बनाम मराठी विवाद को कई बार राजनीतिक रंग भी दिया गया है। कुछ स्थानीय दलों ने हिंदी भाषी प्रवासियों, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों को निशाने पर लेकर हिंदी भाषा पर परोक्ष रूप से प्रहार किया है। इससे न केवल भाषा के नाम पर लोगों में दूरी बढ़ी है, बल्कि महाराष्ट्र की समावेशी छवि को भी आघात पहुंचा है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों, विशेषकर मुंबई, ठाणे, पुणे, और नासिक में बड़ी संख्या में हिंदीभाषी समुदाय निवास करता है। ये लोग महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था, व्यापार, निर्माण और सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परंतु जब इनकी भाषा को दोयम दर्जे का माना जाता है, या उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो यह संविधान की आत्मा ह्राएकता में अनेकताह्म के विपरीत है। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में हिंदी और मराठी दोनों को मान्यता प्राप्त है।

राज ठाकरे के एक मंच पर आने की खबर ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी। 5 जुलाई को होने वाली हिन्दी विजय रैली पर महाराष्ट्र के लोगों की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि मराठी भाषा और संस्कृति के मुद्दे पर सुर में सुर मिलाने वाले उद्धव और राज ठाकरे को सियासी हौसला मिल गया है। जिसे महाराष्ट्र की सियासत में एक नया मोड़ माना जा रहा, लेकिन साथ ही सवाल है कि उद्धव और राज ठाकरे की सियासी केमिस्ट्री कब तक बरकरार रहेगी। हिंदी बनाम मराठी विवाद को कई बार राजनीतिक रंग भी दिया गया है। कुछ स्थानीय दलों ने हिंदी भाषी प्रवासियों, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों को निशाने पर लेकर हिंदी भाषा पर परोक्ष रूप से प्रहार किया है। इससे न केवल भाषा के नाम पर लोगों में दूरी बढ़ी है, बल्कि महाराष्ट्र की समावेशी छवि को भी आघात पहुंचा है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों, विशेषकर मुंबई, ठाणे, पुणे, और नासिक में बड़ी संख्या में हिंदीभाषी समुदाय निवास करता है। ये लोग महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था, व्यापार, निर्माण और सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परंतु जब इनकी भाषा को दोयम दर्जे का माना जाता है, या उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो यह संविधान की आत्मा ह्राएकता में अनेकताह्म के विपरीत है। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में हिंदी और मराठी दोनों को मान्यता प्राप्त है। हिंदी भारत की राजभाषा है और मराठी महाराष्ट्र की राजभाषा। किसी भी राज्य में भाषा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसके नाम पर दूसरी भाषाओं को अपमानित करना न तो संवैधानिक है और न ही नैतिक। भाषायी सह-अस्तित्व के लिये महाराष्ट्र में मराठी को सर्वोच्च स्थान मिले, लेकिन हिंदी भाषा को भी सम्मान मिले, यह संतुलन ही स्वरथ लोकतंत्र का आधार है। स्कूलों में मराठी, हिंदी और अंग्रेजी- तीनों भाषाओं को समुचित महत्व देकर बच्चों में बहुभाषिक दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है। विभिन्न राजनीतिक दल भाजपा एवं केन्द्र सरकार को घेरने के लिये जिस तरह भाषा, धर्म एवं जातिव्यता को लेकर आक्रामक रवैया अपनाते हुए देश में अशांति, अराजकता एवं नफरत को फैला रहे रहे हैं, यह चिन्ताजनक है। महाराष्ट्र में हिन्दी का विरोध आश्चर्यकारी है। आजादी के अमृतकाल तक पहुंचने के बावजूद हिन्दी को उसका उचित स्थान न मिलना विडम्बना एवं दुर्भाग्यपूर्ण है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का

धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।

संपादक: पंकज धर द्विवेदी

संपर्क सूत्र :

ghoonghatkibagawat37@gmail.com